प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

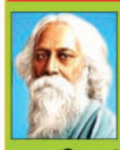

इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए सिर्फ फौज या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है। जैसे की इमाम हुसैन ने कर्बला में किया।

रविन्द्रनाथ टैगोर

वर्ष-06, अंक - 43 (साप्ताहिक) खवासा, शुक्रवार 19 जुलाई 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

एक पेड़ मां के नाम... मां का नाम मुरझाने ना पाए...

माही की गूंज। संजय भटेवरा

झाबुआ। प्रधानमंत्री की देश हित में की गई अपील को पूरा देश तन-मन से और पूरी लगन से पूरा करता नजर आ रहा है। कोरोना काल में चाहे थाली-ताली बजाना हो या फिर दीपक जलाना। यही नहीं स्वच्छता की अपील का भी व्यापक असर हुआ है और अब लोग स्वच्छता को अपनी आदत बना चुके है। इंदौर ने स्वच्छता में लगातार सात बार शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं देश के अन्य शहरों में भी स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है, हर शहर टॉप पर आने का प्रयास कर रहा है।

हाल ही में भीषण गर्मी का दंश झेल चुके भारतवासियों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील की। जिसको लेकर पूरे देश में पर्यावरण के प्रति नई जन चेतना का संचार हुआ है। स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने तो प्रधानमंत्री की अपील को मंत्र मानकर एक ही दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। निश्चित रूप से इस विश्व रिकॉर्ड के लिए इंदौरवासियों सहित हर शख्स बधाई का हकदार है, जिसने इस अभियान में गिलहरी सा योगदान भी क्यों न दिया हो। इंदौर सहित प्रदेश व देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता के साथ बड़े पैमाने पर एक पेड़ मां के नाम... अभियान से संबंधित कई आयोजन हो रहे हैं। जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस अभियान में भागीदारी कर पौधारोपण कर रहे हैं। वेसे तो पौधारोपण कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है अमूमन हर साल मानसून के पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से पौधे लगाने का अभियान चलाया जाता है जो हरियाली अमावस्या तक जारी रहता है। यही नहीं कई शासकीय आयोजन में जनप्रतिनिधि भी जोर-शोर के साथ वृक्षारोपण करते हैं।

एक पौधे को लेकर कई लोगों का फोटो सेशन होता है और उसके बाद उस पौधे की कोई शुध लेने वाला नहीं मिलता है। सोशल मीडिया पर जिसको लेकर कई प्रतिक्रिया सामने आती रही है, कई कटाक्ष आते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। अगले साल फिर वृक्षारोपण की याद आती है और फिर लोगों में फोटो खिंचवाने की होड मच जाती है। यह क्रम पिछ्ले कई सालों से चला आ रहा है। अभी तक हुए वृक्षारोपण में से नाम मात्र के पौधे ही पेड़ बन पाए होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष इस अभियान को भावनात्मकता देने का प्रयास किया है और पेड़ को अपनी मां के नाम पर लगाने की अपील की है, लेकिन पौधे लगाने वाले महानुभावों से निवेदन है की मां का नाम मुरझाने ना पाए। पौधों को लगाने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उस पौधे की कम से कम 5 साल तक देखभाल करें और गर्मियों में उनको पानी पिलाने की समुचित व्यवस्था करें। क्योंकि पौधे को पेड़ बनने पर ही माँ की याद अनुशरण रह सकती है।

मनरेगा को इस अभियान में शामिल करें...

शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जिसके अंतर्गत शासन द्वारा न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। वर्षों से चली आ रही इस योजना के नाम पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं। एक-एक गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गांव की तस्वीर जस की तस है। कोई विकास कार्य नजर ही नहीं आता है। 5 लाख से लेकर 50-50 लाख से अधिक राशि के तालाब एक-एक पंचायत में अनेको तालाब व अन्य करोडो के कार्य विकास व जल संरक्षण के नाम पर मनरेगा में किए गये है यह कार्य पुरी तरह से भ्रष्टाचार की भेट चढ़ चुके है नतिजन अधिकांश तालाबो में बारिश में भी उनमें पानी नजर नहीं आता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो एक पेड़ मां के नाम को मनरेगा योजना से जोड़ दे। जिसमें गारंटी में रोजगार पाने वाले व्यक्ति भी जिम्मेदारी तय कर पाए कि वह उस पौधे को पेड़ बनने तक इसकी समुचित व्यवस्था करें। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा उसका रिकार्ड संधारित किया जाए और प्रतिवर्ष लगाने वाले पौधों की भी उसमें एंट्री की जाए तो निश्चित रूप से इस योजना में हितग्राही के साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो सकती है और मनरेगा योजना जो कि वर्तमान में केवल गड्ढे खोदने की योजना साबित हो रही है... का लाभ भी आम जनता को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।

फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप से बाहर आए

इस वर्ष भीषण गर्मी में सोशल साइटों पर वृक्षारोपण और वृक्षों के महत्व के बारे में देखने और पढ़ने को मिला जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई कि वास्तव में लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील है। कई लोगों ने 10-20 वर्षों के बाद की भयावहता के बारे में भी लोगों को सजक किया। कई लोगों ने एक पेड़ से होने वाले लाभों को गिनाया है, कई लोगों ने वर्तमान में विश्व में कितने पेड़ों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। कई लोगों ने पेड़ों से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन को भी अपने अंदाजी सिलेंडरों में नाप कर उसकी कीमत भी बतला दी।

यानी कुल मिलाकर इन साइटों फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर ऐसा लगने लगा कि, वास्तव में लोग पर्यावरण के प्रति कितने गंभीर और सजग है। लेकिन अब समय है की आभासी दुनिया से बाहर निकल कर कुछ कर दिखाने का। मानसून सीजन प्रारंभ हो चुका है और प्रत्येक देशवासी यह संकल्प ले की वो न केवल एक पौधा लगाएगा, बल्कि उसको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी भी उठायेगा तभी मां के नाम पर पेड़ लगाने की ओर मां के नाम को अमरता प्रदान करने की इस योजना व अभियान की सार्थकता है। नहीं तो अन्य अभियान की तरह ही यह अभियान भी केवल रस्म अदायगी तक ही सीमित रह जाएगी।

आज कोई व्यक्ति इसलिए पेड़ की छाया में बैठा है क्योंकि बरसों पहले किसी व्यक्ति ने पेड़ लगाया था। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छाया की व्यवस्था करें...।

हादसाः चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पांच बोगियां पलटी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़ा हादसा हो गया। गोंडा-गोरखपुर रेलमार्ग पर मोतीगंज के पास चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पांच बोगियां पलट गईं। जिसमें कई लोगो की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल हुए है। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीएम ने जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए।

नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। साथ ही एनटीए को निर्देश दिया कि, अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि, नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की है, जिसके अनुसार अब नीट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बडी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी।

मुल्ला जी-मुल्लाजी नसीहत और खुद फजिहत

धारा 163 को क्या प्रशासन बना रहा अपना हथियार?

निषेधाज्ञा लागू कर तानाशाही करने पर तुला प्रशासन

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो इस देश में विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार आमजन को हासिल है। लेकिन अब 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा कर पाना शायद मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आमजन को अपने विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जैसे मौलिक अधिकारों की भी अनुमति प्रशासन से लेना पड़ेगी। चाहे फिर वह विरोध प्रदर्शन, आंदोलन या धरना प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ ही क्यों न हो। प्रशासन 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बूते आमजन के मौलिक अधिकारों की हत्या करता दिखाई दे रहा है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उपयोग अब प्रशासन अपने बचाव व बुराईयों को छुपाने में करता दिखाई दे रहा है। इससे हालात कुछ ऐसे बन गए है कि, अगर किसी को प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो पहले उसे प्रशासन की ही अनुमति लेनी होगी। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो ठीक वरना यह तय है कि आपकी बात प्रशासन नहीं सुनेगा।

1 जुलाई को नर्सिंग घोटाले के खिलाफ हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की घटना के बाद 3 जुलाई को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टोरेट परिसर में धारा 163 लागू कर दी गई। इससे पहले पुरानी कानून व्यवस्था में धारा 144 का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह धारा 163 लागू होगी। झाबुआ एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का पहला आदेश जारी कर दिया। हालांकि इस समय न तो कोई चुनाव का समय था और ना ही कोई कानून व्यवस्था की स्थिति थी। बावजूद इसके एसडीएम ने कलेक्टोरेट परिसर में धारा 163 को लागू कर दिया। अब एसडीएम के इस आदेश के बाद जो व्यक्ति या संस्था या राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना या व्यक्तिगत ज्ञापन या आवेदन देना चाहेगें तो उसे पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति नहीं दी गई तो फिर आप प्रशासन का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर बावजूद इसके आपने विरोध किया तो फिर यह तय है कि, आपके खिलाफ सीधे तौर पर मामला दर्ज कर दिया जाएगा।

इस तरह की पाबंदिया कलेक्टोरेट परिसर में

कलेक्टोरेट परिसर में अब किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, या ज्ञापन आदि बिना सूचना के नहीं प्रस्तुत कर सकेंगे। अपने साथ किसी तरह की बंदूक लेकर नहीं चलेंगे, लाइसेंस परमिट के सत्यापन को छोड़कर। कोई भी हथियार अपने साथ लेकर कलेक्टोरेट परिसर में नहीं जा सकेंगे। संगठन, राजनैतिक पार्टियां या दल या कोई प्रत्याशी बिना किसी अनुमति के न तो आमसभा करेगा ना कोई रैली निकालेगा और न ही जुलूस का आयोजन कर सकेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था के कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा विशेष रूप् से प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

इस तरह हुई 163 लागू

बीती 1 जुलाई को कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार तक आ गए थे। मगर इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि, कांग्रेस द्वारा किए जा रहे इस आयोजन की किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस घटनाक्रम के बाद 3 जुलाई को झाबुआ एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने 1 जुलाई से लगू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

कलेक्टोरेट परिसर में 163 निषेधाज्ञा यानि तानाशाही राज

अब सवाल यह कि क्या कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी या दल, या फिर कोई आमजन अपने साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, जबकि यह उसका मौलिक अधिकार है। मगर धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा उस पर अब भारी पड़ती नजर आ रही है। प्रशासन ने खुले तौर पर अब इसे अपना हथियार बना दिया है, ताकि कोई भी उसकी अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन न कर सके। मतलब साफ है कि, अगर आपको प्रशासन के खिलाफ भी अगर विरोध प्रदर्शन करना हो तो उसी की अनुमति की जरूरत होगी और यह तय है कि वह किसी भी सूरत में प्रशासन आपको नहीं देगा। मतलब पूरी तरह से तानाशाही राज कलेक्टोरेट परिसर में जिला मुख्यालय पर लागू हो चुका है।

प्रशासनिक कार्रवाई संदेह के घेरे में

प्रशासन की इस निषेधाज्ञा पर यह आरोप कोई हवाबाजी नहीं है। यह प्रमाणित भी होता नजर आ रहा है। प्रशासन की कलेक्टोरेट परिसर में इस तरह निषेधाज्ञा लागू करने को लेकर कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधियो ने अपना विरोध यह कहकर दर्ज करवाया है कि, यह आदिवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। सरकार से लेकर अधिकारी तक लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए है। या फिर आदिवासियों की उठती आवाज से अधिकारी डरे हुए है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि 10 जुलाई को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ के साथ ही उनके दो साथियों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनके विरूद्ध यह कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बगैर 50 से अधिक ग्रामीणों को भ्रमित कर लाने व कलेक्टोरेट परिसर में अशांति फैलाने के साथ कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप है। जबकि आप जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि, आदिवासियों के हक में आवाज उठाने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। प्रशासन के विरोध में जल्द ही जिले में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 10 जुलाई की शाम सिंगाड़ ने अपना दर्द अपने लफ्जों में सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा शेर किया। हम इस बात की कतई पुष्टि नहीं करते कि सिंगाड़ की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट सत्य है, लेकिन इसके बाद प्रशासन का एक दम से एक्शन में आना और सिंगाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि इस मामले पर कलेक्टर ने भी मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में कमलेश सिंगाड़ पर निजी स्वार्थ के चलते लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए है। अब इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही और कौन गलत यह अब भी संदेह के घेरे में है। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर सिंगाड़, विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे वह वाजिब मुद्दा होकर जनहित में था। मगर कलेक्टर के बयान के मुताबित एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर खुद ग्रामीणों से बात कर चुके है। तो फिर यह कैसे संभव है कि, सिंगाड़ के साथ देवझिरी के ग्रामीण तमाम समझाईशों के बावजूद कलेक्टोरेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। या फिर एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर की बात ग्रामीणों के गले नहीं उतरी और आप जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ की बात ग्रामीणों को समझ में आ गई। 10 जुलाई को आप जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने प्रेसवार्ता आयोजित कर कलेक्टर व अफसरों पर आदिवासियों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। सिंगाड़ ने इस दौरान यह भी बताया कि, विरोध प्रदर्शन के लिए एसडीएम से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। इसमें शंका की सुई अधिकतर तो प्रशासन की ओर ही मुड़ रही है। शायद प्रशासन चाहता नहीं है कि, उसके किसी भी कार्य में किसी भी तरह का कोई अड़ंगा लगे या कोई राज उजागर हो। इन्ही सबके चलते 163 निषेधाज्ञा का डंडा घुमाओं और जो विरोध करे उसे एफआईआर करवाकर अंदर डलवाओ।

चाटूकारिता की हद, सोने पर सुहागा

सोने पर सुहागा यह कि इस संबंध में कलेक्टोरेट के अधिकारियों, कर्मचारियों ने चाटूकारिता दिखाते हुए 13 जुलाई को एक ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम एडीएम को दिया। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ पर कलेक्टर से अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए गए तथा कार्रवाई की मांग की गई। 25 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपने हस्ताक्षर युक्त दिए ज्ञापन में बताया कि 9 जुलाई को कमलेश सिंगाड़ ने शासकीय कार्य दिवस में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के जिले के भोले-भाले आदिवासियों को एकत्रित कर असवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। इस दौरान कलेक्टर के कक्ष में कलेक्टर के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया और असंयमित शब्दों का उपयोग किया गया। महिला अधिकारी की भावना को आहत किया गया। जबकि कमलेश सिंगाड़ ने यह व्यवहार अपने साथ होना बताया है।

ज्ञापन के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों ने नहीं ली अनुमति

विडम्बना यह कि खुद कलेक्टोरेट के अधिकारियों, कर्मचारियों ने इस ज्ञापन को देने के लिए कोई अनुमति नहीं ली। अब धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का माखौल खुद कलेक्टोरेट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उड़ाया है। जब इसको लेकर मीडिया ने सत्यनारायण दर्रो से यह सवाल किया तो उनका कहना था अनुमति तो नहीं ली, लेकिन हमें सूचना दी थी। ज्ञापन तो दिया जा सकता है। इस स्थिति में अब अगर प्रशासनिक ताने-बाने पर सवाल ना उठे तो क्यों न उठे। यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ''मुल्ला जी- मुल्ला जी नसीहत और खुद फजिहत''। खुद आदेश जारी करने वाला ही पल्टी मार जाए तो फिर समझा जा सकता है कि धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रशासन ने खुद अपने स्वार्थ के लिए लागू की है, जो कि पूरी तरह से तानाशाही ही कही जाएगी।

समूह संघ ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

समूहों ने स्कूल एवं आंगनवाड़ी में भोजन बंद कर की हड़ताल

माही की गूंज ,पेटलावद।

प्रदेश संगठन भारतीय मजदूर संघ के आव्हान पर पेटलावद क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश के विरुद्ध स्वयं सहायता समूह एवं सांझा चूल्हा रसोयन को आंगनवाड़ियों से हटाने का निर्देश दिया गया था। जिसके विरोध में मंगलवार को स्कूल एवं आंगनबाड़ी में खाना बंद करते हुए एक दिन की हड़ताल कर स्थानीय बीआरसी कार्यालय से महिलाओं ने एक संगठित रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। साथ ही रैली में हमारा काम वापस दो वापस दो, के नारे के साथ कार्यालय भी गूंज उठा , इसके बाद ज्ञापन का वाचन समूह संघ के अध्यक्ष सुरजी भगोरा ने किया एवं तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समूह की रैली में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमजी भूरिया एवं समूह संघ के समस्त संकुल प्रभारी के साथ समूह अध्यक्ष सचिव के साथ स्कूल की रसोयन उपस्थित हुई।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन

महिलाओं ने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन में कहा कि, पिछले 15 वर्षों से स्वयं सहायता समूह एवं सांझा चूल्हा रसोयन आंगनवाड़ियों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान कर रहे हैं। यह आदेश उनके लिए अस्वीकार्य है क्योंकि इससे उनके समूहों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा और बच्चों के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि शासन इस आदेश को वापस नहीं लेता है, तो वे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आदेश महिलाओं के सशक्तिकरण के विपरीत है और इससे लाखों महिलाओ से काम छीन कर शासकीय कर्मचारियों को सौप दिया जाएगा। जिसमें

भ्रष्टाचार होना तय हे। ज्ञापन में महिलाओं ने प्रशासन से निवेदन किया है कि इस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए ताकि उनके समूहों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहें और बच्चों का पोषण सुनिश्चित हो सके।

मंत्री निर्मला भूरिया दे चुकी आश्वासन, नही हटेंगे समूह

विगत दिनों थाना पेटलावद में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई महिला एवं बाल विकास मंत्री, सुश्री निर्मला भूरिया ने महिला समूह संघ को आश्वासन दिया है कि किसी भी समूह को हटाया नहीं जाएगा। इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ, मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग उनके अधीन है और वे किसी का भी बुरा नहीं होने देंगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर अभी मंथन चल रहा है और कोई भी निर्णय महिलाओं के हितों के खिलाफ नहीं होगा।

स्कूल की छत गिरी, मोहर्रम की छुट्टी होने से टला बड़ा हादसा

माही की गूंज, थांदला।

नगर के वागड़िया फलिया स्कूल की छत विगत 8-9 वर्ष से गम्भीर स्थिति में थी जिसकी जानकारी बीआरसी व जिला प्रशासन को दी जा चुकी थी। दयनिय अवस्था में थी यह स्कूल छत जो बुधवार को गिर गई। यह तो अच्छा हुआ की बुधवार को मोहर्रम का अवकाश होने से कोई हादसा नहीं हुआ। यही छत स्कूल संचालित होने पर गिरती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि बच्चे छत के आसपास ही खेलते थे। छत गिरने के मामले मे जानकारी देते हुए बीआरसी संजय सिकरवार ने बताया कि, उक्त भवन विगत 8-9 वर्षो से खाली पड़ा होकर जर-जर हो चुका था एवं वहा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं की जा रही थी।

आवारा सांड कर रहा है घायल

माही की गूंज , करवड़। पेटलावद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम करवड़ में कई दिनों से आवारा सांड घूम रहा हैं जिससे बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने घायल कर दिया है। ग्राम वासीयो में भय का वातावरण बना हुआ है। स्कूल के बच्चे आवारा सांड से डर रहे हैं और स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ दिन पहले जैन समाज की महिला को घायल किया उनका उपचार चल रहा है। इसके पश्चात ग्राम के नाना भाई पवार को घायल किया। इसके बाद बुजुर्ग महिला देवकन्या शर्मा को और शांतिलाल डैरिया को घायल कर दिया जिनका उपचार दाहोद चल रहा है। फिलहाल ग्राम पंचायत इस और ध्यान नही दे रही , आवारा सांड को पकड कर जंगल में छोड़ें या उचित स्थान पर भेजें नहीं तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

पद्मवती नदी का लोटेगा वैभव, साढ़े 3 करोड़ का लगेगा प्लांट

माही की गूंज,थांदला।

थांदला नगर की पुण्य सलीला मां पद्मावती नदी के कायाकल्प को लेकर नगर परिषद प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर नगर परिषद् अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पणदा का कहना है कि, पद्मावती नदी के कायाकल्प को लेकर प्रथम चरण में सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के कार्य की शुरूआत जल्द होने वाली है। इसी को लेकर पद्मावती नदी का वैभव लौटाने को लेकर नगर परिषद 3 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट लगाया जाना है। नगर परिषद थांदला के लगातार प्रयासों से जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से संपर्क किया जिसके चलते प्रथम चरण की स्वीकृति मिली है। जिससे मां पद्मावती नदी में मिल रहे नालों के सीवेज को नगर से बाहर ले जाकर के ट्रिटमेंट किया जाएगा। यह कार्य नगर विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

फ्लोटिंग इंटेकवेल से जल प्रदाय में मिलेगकी मदद

नपाध्यक्ष श्रीमति लक्ष्मी पणदा ने बताया कि, नगर परिषद् के बढ़ते आकार को देखते हुए नगर में अमृत सरोवर 2.0 योजना के अंतर्गत जलप्रदाय के अंतर्गत 2 करोड़ 65 लाख 98 हजार रुपए की लागत से शिव सागर तालाब पर फ्लोटिंग इंटेकवेल लगाया जाना है। जिससे उसमें कम पानी होने पर गहराई से पानी खिंचा जा सकता है। जिसके चलते जल प्रदाय की समस्याएं कम होगी। साथ ही नगर में 700 के करीब नए कनेक्शन लगेंगे। जिसमें एक बड़ी टंकी का निर्माण होना है। इसके अतिरिक्त नई तकनीक स्काडा सिस्टम लगाया जाना है। जिससे जल प्रदाय लाईन में लीकेज होने पर स्वतः पता लग जाएगा।

परिषद के पूर्व पार्षद एवं वार्ड 6 के प्रतिनिधि समाजसेवी सचिन सोलंकी ने बताया कि, मां पद्मावती नदी गहरीकरण एवं शुद्धिकरण के अनेकों प्रयास पूर्व में हुए है। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पणदा एवं उपाध्यक्ष पंकज राठौर के नेतृत्व में भाजपा की परिषद ने यह काम करके दिखाया है। अमृत योजना के माध्यम से नगर में मां पद्मावती नदी के किनारे बह रहे नालों को अलग-अलग स्थान से मजबूत वाटर बॉडी में सम्मिलित किया जाएगा। सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट को लेकर परिषद के पदाधिकारियों ने महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया व वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान का स्वागत कर आभार प्रकट किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाभर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भूमिका आशीष सोनी का भी सराहयनीय प्रयास रहा। विकास कार्यों की स्वीकृति पर पार्षदगण ज्योति जितेन्द्र राठौर, धापू वसुनिया, कन्नू मोरिया, जगदीश प्रजापत, वंदना सुधीर भाभर, नसीम बानो, अखिल जैन, संदीप डामोर ने भी खुशी जाहिर की। मंगलवार को नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पणदा, समाजसेवी सचिन सोलंकी अजा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पार्षद राजू धानक, पार्षद समर्थ उपाध्याय ने नगर के अन्य कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने का पत्र दिया। इस मुलाकात में नगर के एससी वार्ड नंबर 9 के बावड़ी मंदिर के सामने जल भराव की समस्या को लेकर अवगत करवाया गया। जिस पर अजा कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देकर प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद की इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही।

'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' के तहत जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन

माही की गूंज, शाजापुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संतोष टैगोर के मार्गदर्शन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके तहत प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान व परियोजना अधिकारी सुश्री नेहा चौहान ने ग्राम खेड़ा पहाड़ व खेड़ा में लाड़ली बहनाओं व स्वसहायता समूह की महिलाओं के हाथों पौधारोपण करवाया। इस दौरान सुश्री चौहान ने महिलाओं को बालिकाओं की शिक्षा निरंतर रखने के लिए प्रेरित किया व पर्यवेक्षक प्रिया गोस्वामी ने स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी दी। पर्यवेक्षक ललिता अहिरवार ने ग्राम सटेंडी में मंगल दिवस के अवसर पर अन्नप्राशन संस्कार आयोजित कर बच्चों के वज़न का सत्यापन किया एवं गर्भवती महिलाओं के घर पौधारोपण किया। पर्यवेक्षक श्यामा तोमर ने सेक्टर लाहौरी में पौधारोपण किया। पर्यवेक्षक किरण परमार ने जलोदा आंगनवाड़ी केंद्र एवं परियोजना अधिकारी पंकज दवे द्वारा गुलाना के आंगनवाड़ी केंद्र पर पौधारोपण किया गया।

जिला पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी का हुआ स्नेह मिलन समारोह

माही की गूंज, बामनिया।

जिला पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी का स्नेह मिलन समारोह बामनिया के समीप स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर रामपुरिया पर आयोजित किया गया। आयोजन में जिला पत्रकार संघ के तत्वावधान में एक पेड मां के नाम कार्यक्रम के तहत पोधा रोपण कर पर्यावरण समृद्धि के महायज्ञ में अपनी आहूति दी गई। आयोजन के दूसरे चरण में जिले के विभिन्न स्थानों से आए पत्रकारों ने संगठन को लेकर आपसी विचार विमर्श भी किया एवं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयोजन में मुख्यअतिथि के रूप में पेटलावद एसडीएम अनिल कुमार राठौर ने जिला पत्रकार संघ की विभिन्न इकाईयों के पदाधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में जामुन, आंवला, नीम करंज, पीपल आदि वृक्षों का पौधारोपण किया गया। एसडीएम का पुष्पमाला से स्वागत संघ के संरक्षक मनोज चतुर्वेदी, हरिशंकर पंवार, संजय भटेवरा, जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, महासचिव अक्षय भट्ट आदि पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने उदबोधन में एसडीएम अनिल कुमार राठौर ने कहा कि, इस समय पूरी दुनिया वैश्विक तापक्रम वृद्वि की समस्या से जूझ रही है। जिला पत्रकार संघ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर अपनी लेखकोत्तर भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार तटस्थ और पारदर्शी ढंग से जनससमयाओं पर लिखते है तो प्रशासन भी जनहित के कार्य करने में सफल होता है । उन्होंने पत्रकारों से अपील की,

कि वे जनहित के मुददों को संवेदनशीलता के साथ उठाए । पोध रोपण कार्यक्रम के पश्चात जिला पत्रकार संघ पदाधिकारियों एवं विभिन्न इकाईयों के अध्यक्षों व जिला प्रतिनिधियों सहित कार्यकारिणी की एक महती बैठक आयोजित की गई। जिसमें संघ के सांगठनिक मुददों, सदस्यता विस्तार कार्यक्रम, एकजुटता तथा पत्रकार कल्याण के लिए संघ की दिशा निर्धारण जैसे विषयो पर गहन विचार मंथन किया गया। बैठक को सम्बोधित करते हुए संघ के संरक्षक मनोज चतुर्वेदी ने कहा कि, जिला पत्रकार संघ वर्षों से अपने सदस्यों के साथ हर कदम पर खडा रहता है आगे भी संघ के हर साथी के साथ है।

संरक्षक हरिशंकर पंवार ने कहा कि, मौजूदा समय में पत्रकारिता संक्रमण काल से गुजर रही है ऐसे में हमें संगठन से अपने जुडाव को लेकर अलग ढंग से सोचना पडेगा। संरक्षक संजय भटेवरा ने कहा कि, अन्य संगठनों के द्वारा बद नियती के साथ संघ को कमजोर करने के उदेश्य से पद दिए जाने के साथ जिला पत्रकार संघ के साथ समानन्तर जुटाव की समस्या घातक सिद्व हो रही है।

जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि, जिला पत्रकार संघ जिले का सबसे पुराना एकमात्र संगठन है जिसकी जिले भर में 40 इकाईयां है और सभी इकाईयों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य इस वृहद परिवार के अभिन्न अंग है। संगठन की मजबूती, एकता और तटस्थता को लेकर जल्द ही जिले भर में सदस्यता विस्तार अभियान चलाया जाएगा जिसमें सदस्यता फॉर्म भरवाकर परिचय पत्र जारी करने का कार्य किया जाएगा। महासचिव अक्षय भट्ट ने कहा कि, जिला पत्रकार संघ आतंरिक लोकतंत्र के सिद्वांत पर संचालित होता आया है आयोजन में संगठन के मार्गदर्शक रहे वरिष्ठ पत्रकार स्व. महेशचन्द्र जानी की स्मृति में प्रतिवर्ष जिले के पत्रकारों के लिए सतत क्रियाशील पत्रकारिता पुरूस्कार दिए जाने की घोषणा उनके सुपुत्र एवं पत्रकार मनोज जानी द्वारा की गई। आयोजन के अंत में सहभोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन संरक्षक हरिशंकर पंवार द्वारा किया गया। आभार बामनिया नगरध्यक्ष जितेन्द्र वैरागी द्वारा व्यक्त किया गया।

पुलिस पर आरोपः मामूली विवाद में बेटे को बचाने आई मां की मौत, परिजनो ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम

माही की गूंज, राजगढ़ (ब्यावरा)

जिले के खुजनेर थाना क्षेत्र के बखेड़ गांव में बुधवार की देर शाम हुए मामूली विवाद में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही दबंगों पर हत्या और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए है। वही गुरुवार को महिला का शव सड़क पर रखकर पचोर से जीरापुर मार्ग बंद कर दिया गया।

जानकारीनुसार यह पूरा घटनाक्रम बुधवार की देर शाम का बताया जा रहा है। जिसमे कहा जा रहा है कि, बखेड गांव के अनार सिंह का उसी के पड़ोसी गौरीलाल के साथ विवाद हो गया,और गौरिलाल व उसके परिवार के लोग अनार सिंह से मारपीट करने लगे। विवाद होता हुआ देख अपने बेटे को बचाने के लिए आई अनार सिंह की मां धापू बाई के साथ गौरीलाल के परिवार व महिलाओ ने मारपीट शुरू करदी और देखते ही देखते महिला को इतना पीटा गया की उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृत महिला के परिजनों का आरोप है कि, जब वे इस मामले की शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे, तो पुलिस ने उनकी सुनवाई नही की और आरोपियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नही किया गया। साथ ही पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात कार्यवाई करने की बात की जा रही है। उसी को लेकर गुरुवार को मृत महिला के परिजन थाने के सामने एकत्रित हुए और जीरापुर-खुजनेर मार्ग पर मृत महिला का शव रखकर जाम लगा दिया।

मामले में खुजनेर थाना प्रभारी अनिल राय का कहना है कि, मृत महिला के मामले में उसका पीएम करवाकर मर्ग कायम किया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

इंसानियत की मिसाल इमाम हुसैन की याद में थांदला में निकला ताजीये का जुलूस

माही की गूंज, थांदला।

पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाए गए। 7 जुलाई से इस्लामिक साल का शुरू हो गया था, पहला महीना मोहर्रम का होता है। मोहर्रम महीने की 10 तारीख़ को आशूरा का दिन कहते है। आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन को कर्बला में शहीद किया गया था। इस्लाम धर्म के लोग इसे मोहर्रम त्योहार के रूप में नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन की याद के रूप में मनाते हैं, मोहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक रोजाना ईशा की नमाज़ के बाद गौसिया जामा मस्जिद में मौलाना इस्माईल बरकाती साहब व कारी मुश्ताक बबीबी साहब द्वारा शहादातनाममा सुनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी आशूरा के दिन सुबह 10 बजे जामा मस्जिद में दुआ ए आशूरा पढ़ाई गई। ताजिए का जुलूस दोपहर 2 बजे जामा मस्जिद से शुरू हुआ और गांधी चौक में सभी ताजिए एकत्रित होने के बाद जुलूस पुरानी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पहुंचा। चौराहे पर हुसैनी अखाड़ा खेला गया। हुसैनी अखाड़े के उस्ताद शाकिर शेख व शोएब खान (भुरू) द्वारा अपने शिष्यों के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैरात अंगेज करतब दिखाए गए। हुसैनी अखाड़ा खेलने के बाद ताजिए का जुलूस बोहरा मोहल्ला होते हुए अस्पताल चौराहे पर पहुंचा। जहां से आजाद चौक, गांधी चौक होते हुए करबला पहुंचा। रास्ते भर में ताजिए पर मन्नतधारीयों ने अपनी मन्नतें पूरी की।

ताजिये के जुलूस में मुस्लिम पंच सदर हश्मतुल्लाह पठान, फरजमान पठान, ताजिया बनाने ज़ाकिर शेख (राजापुरा) मोहम्मद अकबर खान, ज़ाकिर शेख, शहजाद कुरेशी, मसीद, आशिक शेख, साबिर रंगरेज, रिज़वान खान, रियाज़ खान, हुसैनी कमेटी के सदर शाहिद निजामी आदि मुस्लिम समाजजन मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

मुस्लिम पंच सदर हश्मतुल्लाह पठान ने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि ताजिए के जुलूस को लेकर प्रशासन की तरफ अच्छा बंदोबस्त किया था। पुलिस विभाग, नगर परिषद की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी जिससे जुलूस में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रही।

यजीद ने इमाम हुसैन को किया था कत्ल

अरब के इतिहास में दर्ज ये एक ऐसी जंग है, इमाम हुसैन से लेकर 6 महीने के मासूम अली असगर को भी तीर मारकर शहीद कर दिया गया था। इंसानियत और सत्य की लड़ाई में हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ कर्बला के मैदान में तीन रोज तक बिना पानी और खाने के भूखे रखकर जंग लड़ी थी। यहां तक की छोटे-छोटे बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया था। उस समय के शाम (अरब का एक देश) के बादशाह यजीद ने मनावता पर बर्बरीयत की सारी हदें पार कर दी थी।

अनदेखीः रोड नहीं बनने से ग्रामीणों को बारिश में होती है परेशानी

मामलाः थांदला जनपद की ग्राम पंचायत रतनाली का

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सोलंकी

एक तरफ प्रदेश सरकार गाव-गाव व फलिये-फलिये में सड़क बनाने के वादे कर रही है। सरकार की योजनानुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री सुधर ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में सड़क बनाई जाती है। लेकिन झाबुआ जिले में कई ग्रामीण अंचलों में आज भी सड़क नहीं बन पाई है जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी होती है खासकर एसे स्थानो पर बारिश के समय ज्यादा परेशानियों से झूझना पड़ता है। लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई पहल नहीं की जाती। जिससे ग्रामीणों को बारिश के समय में रास्ते में आने-जाने के साथ ही कीचड़ आदि का सामना करना पडता है।

आजादी के बाद अब तक सुगम सडक की राह जो रहै थांदला जनपद के रतनाली के ग्रामीण लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नही है। ग्राम पंचायत रतनाली में जहां रतनाली से बिल्लीपाड़ा फलिया होते हुए अमरगढ़ रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। लेकिन यहां कभी भी न तो पंचायत द्वारा ध्यान दिया गया न ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया गया न ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ध्यान दिया। जिससे आज भी ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानियों से गुजरना पड़ता है, साथ ही मिट्टी अधिक होने से बारिश के समय में ग्रामीणों को फिसलने का डर भी अधिक रहता है जिससे ग्रामीण खुद निजी खर्चे से रोड पर बड़े-बड़े पत्थर डाल रहे है और मोरम डाल कर सुगम रास्ता बनाने का प्रयास निजी खर्च के साथ कर रहे है।

ग्रामीण मोरसिंह अमलियार, धना वजेसिंह बहादुर आदि ग्रामीणों ने बताया कि, हम अपने निजी खर्चे से बड़े-बड़े पत्थर के साथ कीचड़नुमा गड्ढो में डाल रहे हैं जिससे हमें आने-जाने में परेशानी नहीं हो। काफी लोग इसी रास्ते से आना-जाना करते हैं साथ ही नजदीक अमरगढ़ रेलवे स्टेशन भी है वहां तक भी हम जाते हैं लेकिन फिर भी न तो ग्राम पंचायत में न ही संबंधित अधिकारियों ने इस ओर रोड बनाने की अब काई पहल की है। शासन व प्रशासन की अनदेखी आज तक हमारा जीना दुश्वार हो रहा है।

सचिव गौरसिंग मैड़ा ने बताया, पंचायत द्वारा हमने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है, वहां वास्तव में समस्या आ रही है यह हम भी जानते है। जैसे ही रोड स्वीकृत होगी हम वहां रोड शुरू कर देंगे।

थांदला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेंद्र बारोडीया ने बताया, पंचायत अपने स्तर से रोड का निर्माण करवा सकती है, सुदर ग्रामीण सड़क योजना में अभी रोड कहा बन रहे हैं, और मैं मामला फिर भी दिखाता हूं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

सागवा कलस्टर सबइंजीनियर अतुल डामर ने कहा, मेरे पास दो क्लस्टर है एक तो परवलिया एक सागवा। मुझे जानकारी में है कि, रतनाली में रोड नहीं बना है और वहां ग्रामीणों को समस्या भी हो रही है, आप बताएं वहां क्या करना है ? अभी तो टीएस नहीं हो सकता क्योंकि शासन स्तर से अभी रोड नहीं बन रही है, वहां के ग्रामीणों को समस्या हो रही है जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा।

मेंटेनेंस के नाम पर उठे सवाल, कभी भी किसी भी समय हो जाती है बिजली कटौती

माही की गूंज,खवासा।

लगातार 24 घंटे बिजली देने का दावा सरकार द्वारा किया जाता है। वहीं सिंचाई के लिए 10 घंटे व घरेलू के लिए 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान सरकार व शासन द्वारा तय किया गया है तो वहीं बिजली विभाग इन नियमों को दरकिनार करते हुए ग्रामीण अंचलों में बने फीडर सेपरेशन में कभी बत्ती गुल हो जाती है तो कभी कम वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण झूझ रहे है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है।

ऐसा नहीं है कि संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं है सब जानकर अनजान बनकर कम वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों को रूबरू होने पर विवश हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश विद्युत वितरण क्षेत्र खवासा अंतर्गत आने वाले रत्नी फिटर के भामल, परवाड़ा,रत्नी आदि ग्रामीण अंचलों में सामने आया। जहां जरा सी बारिश में ही लाइन कट हो जाती है, तो वही कभी कम वोल्टेज तो कभी मीटर में लुका छुपी की परेशानी सामने आ रही है। वही वॉल्टेज कम होने पर मीटर में लाइनसाफ दिखाई देती है लेकिन घरो मे लाइन नहीं चल नहीं पाती हैं। हमेशा ग्रामीण अंचलों में कम वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों को दो-चार होना पड़ रहा हैं। ऐसा नहीं है कि, खवासा में पदस्थ कनिष्ठ उपयंत्री को अवगत नहीं है उनको सब जानकारी होने के बाद भी ग्रामीणों की समस्याओं को अनसुना करके अपने कार्य से मुक्ति पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को हल ही नहीं कर पा रहे है। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम भामल में मंगवार रात्रि साड़े 3:30 बजे के मध्य सामने आया जहां ग्राम भामल में 3:30 बजे ही लाइट डिम हो गई तो रात्रि में मच्छरों से ग्रामीणों को परेशानी हुई। वही कम वोल्टेज की समस्या इस क्षेत्र में हमेशा से बनी हुई है जिससे ना तो पंखे चल पा रहे हैं ना ही कूलर आदि की हवा दे पा रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित कटौती करता है लेकिन थोड़ी सी बारिश में ही विभाग द्वारा किया गया मेंटेनेंस की पोल खुल जाती है।

किसान के वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर जिले से किस का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें किसान अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां किसान ने शिकायत की सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए गिड़गिड़ाते हुए शिकायत सुनने की गुहार लगाई थी।

इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जहां घटनाक्रम का वीडियो देखने के बाद कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई की है।

मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया की, जनसुनवाई के दौरान आवेदक शंकर लाल पिता फूलचंद द्वारा आवेदन दिया गया था।सहानुभूति पूर्वक आवेदन लिया तथा मामले को सुना। जिस भूमि के संबंध में आवेदन दिया गया था। उस भूमि पर आवेदक स्वयं काबिज हैं। उक्त आवेदन का परीक्षण करवाया गया।परीक्षण के बाद आवेदन के संबंध में संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम सुरखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 604 एवं 625 कुल रकबा 3.52 हेक्टर संयुक्त खातेदार शंकर लाल अनोखी लाल भगवान बाई रेशमबाई पिता फूलचंद 1/2 एवं संपतबाई बेवा घासीराम कारूलाल रामलाल प्रभु लाल मांगी बाई पार्वती बाई पिता घासी हिस्सा 1/2 पर दर्ज रही। जिसमें से सह खातेदार संपतबाई इत्यादि द्वारा 2010 में अपने हिस्से की भूमि अश्विन पिता नारायण देशमुख को विक्रय की गई। तथा उक्त भूमि पर क्रेता अश्विन द्वारा कब्ज़ा नहीं लिया गया।

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, आवेदक शंकर लाल पिता फूलचंद द्वारा 1/2 भूमि जो कि आवेदक के हिस्से की है उस पर वर्तमान में काबिज है एवं सह खातेदार संपतबाई इत्यादि द्वारा जो भूमि 2010 में विक्रय की गई थी, उक्त भूमि पर भी शंकर लाल पिता फूलचंद का कब्जा आज दिनांक तक है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति/भू माफिया द्वारा आवेदक शंकरलाल पिता फूलचंद की जमीन पर कब्ज़ा नहीं किया जा रहा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा उस पर प्रशासन द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जवाबदारों की अनदेखीः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर बने रोड पर दौड़ रहे ओवरलोड डंपर

माही की गूंज,खवासा।

ग्रामीण अंचलों में बने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनाए गए रोड पर 8 टन से अधिक लोंडींग वाले कोई भी वाहन परिवहन नहीं हो सकते है। लेकिन भामल से बेडावा मार्ग पर औवरलोड गिट्टी से भरे डंपर धड़ल्ले से चल रहे हैं जिसमें देखने वाला कोई नहीं है।

बिना जांच पड़ताल के धड़ल्ले से अवैध तरीके से गिट्टी राजस्थान के बड़ीसरवा ग्राम पंचायत के फलीया पाणदा मे मुख्यमंत्री बजट घोषणा तहत वर्ष 2023 -24 मद से मिसिंग लिंक सड़क निर्माण योजना सरोना से पाणदा व्याहा पटेला तक 3 किलोमीटर मे यह रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाड़ा(राजस्थान) के माध्यम से ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही। ठेका बालाजी एंटरप्राइज को मिला हुआ है। जिस कम्पनी को ठेका मिला उसके द्वारा डंफर ओवरलोड चलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बने रोड पर ओवरलोड चलाकर गिट्टी को ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी न तो राजस्व विभाग न ही पुलिस प्रशासन न परिवहन विभाग के साथ ही रोड संबंधित अधिकारी इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे है। वही रायल्टी संधित कोई जाच भी नही हो रही है जिसमें ठेकेदारों के हौसले बुलंद हो रहे है। जानकारी अनुसार मादलदा ग्राम पंचायत के फलिया कलदेला में जो क्रेशर मशीन चल रही है वहां से गिट्टी भरकर समीपपस्थ राजस्थान के बड़ी सरवा मे बडी मात्रा में सप्लाई हो रही है। गिट्टी अवैध तरीके से पहुंच रही है या वैध तरीके से पहुंच रही है इस और खनिज विभाग की ध्यान नहीं दे रहा है।तो जितनी गिट्टी की रॉयल्टी कट्टी है उससे अधिक में डंपर ओवरलोड भरे जा रहे हैं जो ग्रामीण अंचलों में बनाए गए सड़कों को क्षतिग्रस्त के साथ ही नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यह डंपर अनगिनत स्पीड के साथ धड़ल्ले से ग्रामीण अंचलों में गुजरते हैं जिससे कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जु तक नहीं रेंग रही है। वहीं जहां-जहां क्रेशर प्लांट संचालित हो रहे हैं वहां से कितनी-कितनी मात्रा में गिट्टी जा रही है कितनी मात्रा मे चुरी(डस्ट) कहां से कहां जा रही है। साथ ही संबंधित रॉयल्टी कितनी कटाई है इसकी भी खनिज विभाग कभी जांच नहीं करता है। जिससे क्रेशर प्लांटं नियमों को दरकिनार करते हुए संचालित किये जा रहे हैं। कभी कभार अधिक शिकायत होने के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों की आंखें खुलती है और वह भी मात्र शहर की तरफ बने रोड पर जाकर खानापुर्ती के साथ डंपरों को पकड़ कर अपनी इति श्री करते है। जबकि ग्रामीण अंचलों में इस तरह से ओवरलोड डंपर धड़ल्ले से निकलते हैं।

एमपी जीएसवाय झाबुआ-धार महाप्रबंधक अनुपम सक्सैना बात करने पर कहते है, आपके द्वारा मामला बताया गया है तो मैं जल्दी संबंधित इंजीनियर को कहकर मामला दिखवाता हूं और जल्द ही ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारी संघ के शपथ विधि समारोह में प्रतीक चिन्ह का हुआ अनावरण

माही की गूंज , पेटलावद।

तहसील व्यापारी संघ (काटन एवं ग्रेन) के पदाधिकारियों का शपथ विधि समारोह स्थानीय निजी गार्डन में संरक्षक सुरेश निमजा, व्यापारी संघ अध्यक्ष महावीर भंडारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तहसील व्यापारी संघ के समस्त सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में उपाध्यक्ष नरेंद्र कोठारी झकनावद, महेंद्र तलेसरा सारंगी, राहुल पटवा बामनिया, राजेंद्र खुनिया रायपुरिया, अनिरुद्ध अग्रवाल पेटलावद एवं संयुक्त सचिव के रुप में पंकज पी पटवा एवं विनोद बाफना पेटलावद, कोषाध्यक्ष श्रेणिक कोठारी झकनावद एवं मीडिया प्रभारी विपुल लोढ़ा बरवेट ने पदभार ग्रहण किया। समस्त नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत संघ अध्यक्ष महावीर भंडारी ने पुष्प माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संघ संरक्षक सुरेश निमजा का सम्मान अध्यक्ष श्री भंडारी ने किया। इस मौके पर व्यापारी संघ के प्रतीक चिन्ह का अनावरण पदाधिकारियो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनोद बाफना एवं आभार कोषाध्यक्ष श्रेणिक कोठारी ने माना।

विवादित नायब तहसीलदार की हुई विदाई, विजेंद्र कटारे होंगे नए तहसीलदार

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

अपनी पदस्थापना से ही चर्चा और विवाद में रहें सारंगी में पदस्थ नायब तहसीलदार वरुण उपाध्याय की आखिरकार विदाई हो ही गई। वही नए नायब तहसीलदार के रूप में विजेन्द्र कटारे को पदस्थ किया गया है। ग्राम पंचायत सारंगी के कार्यों में अड़ंगा डालना उपाध्याय साहब को भारी पड़ गया। पंचायत आबादी भूमि में अनावश्यक दखल देकर दबाव बनाने की रणनीति साहब को ही भारी पड़ गई, और आखिरकार साहब को जाना पड़ा। इस ट्रांसफर ने एक बार फिर सारंगी की मजबूत राजनीति की पकड़ को साबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि, पिछले 15 माह में सारंगी में 7 नायब तहसीलदार बदले जा चुके है और अब आशा है कि, नए साहब सभी से सामंजस्य बिठाकर अपने लंबे कार्यकाल तक टिके रहेंगे।

ठेकेदार की बल्ले-बल्ले : 49 लाख से अधिक राशि से निर्मित आरोग्य केंद्र में किया जा रहा भ्रष्टाचार

माही की गूंज, भामल।
नारायण पालरा

सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास करके समुचित लाभ देने के लाख दावे करती है। वही दुसरी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व ठेकेदार प्रणाली इसको पलीता लगाती नजर आती है। इन दिनों ग्रामीण अंचलों में धडल्ले से आरोग्य केंद्र बनाए जा रहे है। इन आरोग्य केंद्र पर ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को समुचित लाभ मिले इसी उद्देश्य के साथ उनकी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। बताते हैं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर भोपाल द्वारा बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा निर्माण की लागत 49 लाख से अधिक है। इसमें अस्पताल के भवन के साथ ही सीएचओ व एएनएम के रहने आदि के साथ इस अस्पताल का संचालन करेंगे। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ संबंधित बीमारियों का इलाज करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ सभी जगह यह भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक भवन थाना जनपद की ग्राम पंचायत मादलदा मे भी स्वास्थ विभाग द्वारा बनाया जा रहा है लेकिन इसमें भी खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। विभाग की अनदेखी व विभागीय इंजीनियर की लापरवाही कहे या उनकी देखरेख में ही यह सब किया जा रहा है? यहा ठेकेदार खुले आम डस्ट चुरी का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार कर रहा है, तो निम्न व घटिया क्वालिटी की रेत व सीमेंट इस्तेमाल करके जल्द ही कार्य पूरा करने की होड़ में लगा है। लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार इंजीनियर इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे है।

निम्न व घटिया स्तर का हो रहा कार्य।

वही ग्रामीणों का कहना है जिस स्टीमेंट के अनुसार कार्य होना चाहिए उसमें भी कमी है। स्टीमेंट के अनुसार 80 बॉय 80 का भवन होना चाहिए जिसमे सीएचओ आवास, नल-कूप खनन एवं बाउंड्रीवाल का निर्माण भी करना है। माही की गूंज प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर जिस सामग्री से कार्य किया जा रहा था उसे देखने पर ही सामने आया कि, कम सीमेंट के साथ ही निम्न व घटिया स्तर की डस्ट का उपयोग किया जा रहा है।

कारीगरों से चर्चा की तो बताया कि, यहां इंजीनियर साहब तो कभी देखने नहीं आते हैं यहां ठेकेदार की साईट के सुपरवाइजर सुकेश सोनी आते हैं उनकी देखरेख में ही कार्य चल रहा है, वह हमें जैसे सामग्री देते हैं हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उन्होंने डस्ट चुरी आदि इस तरह से दी है तो हम क्या करें हम तो मजदूर हैं हमें ठेकेदार द्वारा जैसी सामग्री दी जाएगी वैसा ही हम इस्तेमाल करेंगे। छत से अभी ही पानी टपकने लगा है लगभग 80प्रतिशत काम हो चुका है। तो वही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि, जो दरवाजे खिड़की लगाए जा रहे हैं वह निम्न व घटिया चद्दर के लगाए गए हैं अगर इसकी जांच की जाए तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। वही भवन निर्माण में जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया उसमें लैब में टेसि्टंग की जाए तो यह मैटेरियल निम्न व घटिया ही आएगा।

सीएचएमओ झाबुआ बीएस बघेल ने कहा, मैं जानकारी लेता हूं वहां किस स्तर का कार्य हो रहा है। फिर भी आप एक बार विभागीय इंजीनियर से चर्चा कर ले मैं जानकारी लेकर मामला दिखवाता हूं।

मामले में ठेकेदार के सुपरवाइजर सुकेश सोनी से उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।

मामले में नेशनल हेल्थ मिशन झाबुआ के प्रभारी सब इंजीनियर पवन रोमेड से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया।

संपादकीय

आत्ममंथन करे भाजपा

हालिया लोकसभा चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन के कुछ ही समय बाद सात राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक अपनी कामयाबी से खासा उत्साहित है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने तेरह में से दस सीटें जीत ली हैं। जहां कांग्रेस ने चार सीटें जीती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी चार सीटें जीती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम सीट जीती है तो डीएमके ने तमिलनाडु में विक्रवंडी निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की है। भाजपा को हिमाचल प्रदेश व मध्यप्रदेश में एक-एक सीट मिली है तो बिहार में एक निर्दलीय जीता है। हालांकि, यह एक हकीकत है कि देश में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में मतदाता अलग-अलग पैटर्न से वोट देता है। तमाम स्थानीय मुद्दे भी विधानसभा चुनाव में असर डालते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव परिणामों की स्थिति को देखते हुए भाजपा आत्ममंथन के लिये मजबूर जरूर होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि इस साल के अंत तक जहां हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी दस विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने हैं। भाजपा के लिये चिंता की बात यह भी होगी कि जिस उत्तराखंड में उसकी सरकार है और हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां दो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में वह क्यों हारी। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड व हिमाचल की जीत कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे दोनों राज्यों में भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में तेरह में सिर्फ तीन सीटें जीत पायी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिये यह राहत की बात होगी कि उनकी पार्टी ने उपचुनाव में सफलता हासिल की है। दूसरी ओर हिमाचल में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत की सांस ले सकते हैं कि चुनाव परिणामों के बाद उनकी सरकार सुरक्षित हो गयी है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल में दीदी का ही एकछत्र राज्य चलेगा। राज्य में टीएमसी ने चार सीटें जीती हैं और तीन सीटें भाजपा से छीनी हैं। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। बहरहाल, केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के तुरंत बाद आए उपचुनावों के नतीजे निस्संदेह भाजपा को असहज करने वाले ही हैं। वहीं संसद के हालिया सत्र में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले पुनर्जीवित विपक्ष के लिये उपचुनाव के नतीजे शुभ संकेत ही कहे जा सकते हैं। हालांकि, विपक्षी खेमे के लिये यहां आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश ज्यादा नहीं है क्योंकि भाजपा भारी बाधाओं के बावजूद चुनाव जीतने का दमखम जरूर रखती है। बहरहाल, यह भाजपा के लिये भी ईमानदारी से आत्ममंथन करने का वक्त है ताकि उसे पता हो सके कि पार्टी की नीतियों में कहां चूक हो रही है। साथ ही यह भी कि उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। बहरहाल, इन चुनाव परिणामों का एक पहलू यह भी है कि मतदाताओं ने उत्तराखंड, हिमाचल व पंजाब में दलबदल करने वाले नेताओं को सबक भी सिखाया है। उत्तराखंड की चर्चित बद्रीनाथ सीट को कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है। उसके सिटिंग एमएलए ने पाला बदलकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। हिमाचल प्रदेश में रोचक परिदृश्य उभरा है जहां देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी चुनाव जीत गई हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी सदन में एक साथ होंगे। वहीं अब चालीस विधायक होने से सुक्खू सरकार पर बना वह संकट टल गया, जो कुछ माह पूर्व राज्यसभा चुनाव के वक्त पैदा हो गया था। हां, इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट भाजपा ने छीन ली है। बहरहाल, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड के आसन्न विधानसभा चुनाव व यूपी के उपचुनावों के दृष्टिगत हालिया उपचुनाव परिणाम भाजपा को विचलित करने वाले जरूर हैं।

शिक्षा के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का समय

यह सवाल अकसर सामने आ खड़ा होता है कि क्यों शिक्षा पर लिखना जारी रखा जाये। शायद, इसलिए कि 'शिक्षा' को लेकर जो प्रचलित परिभाषाएं समाज ने बना रखी हैं, उनसे सहमत होना मुश्किल है। शिक्षा के अर्थ, वर्तमान युग में आम समझ के अनुसार मुख्यतः तीन हैं: (अ) शिक्षा एक प्रकार का 'प्रशिक्षण' है या 'कौशल सीखने' का जरिया (ब) शिक्षा एक किस्म से पायदान-दर-पायदान चढ़ते हुए सीखना है या यह वह राह है जिससे होकर कोई एक खास शैक्षणिक विशेषज्ञता वाली विधा में 'विशेषज्ञ' बनता है (स) यह किसी छात्र को एक 'संसाधन' में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग किसी आर्थिक-सैन्य-तकनीकी प्रयोजन में हो। लेकिन फिर, शिक्षा को लेकर रखे गए ऐसे संकुचित, उपयोगितावादी, तकनीकी रुख से असहज होना स्वाभाविक है। कारण यह कि यदि शिक्षा हमारे अंदर मानवीयता, सौंदर्य बोध, नैतिकता, आध्यात्मिकता की समझ को सक्रिय न कर पाए तो यह खराब एवं खतरनाक बनी रहेगी, भले ही यह देश की आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी के लिए 'कुशल' श्रम शक्ति क्यों न पैदा करती हो या तकनीकी-सैन्य क्षेत्र के लिए 'मानव संसाधन' पैदा करने वाली हो या फिर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी को 'टॉप रैंकिंग' दिलवाने हेतु हजारों की संख्या में रिसर्च पेपर तैयार करने वाली हो।

इस मामले में सख्त रुख की दरकार है। यह कहना हिचक वाली बात नहीं कि इस किस्म की मशीनी शिक्षा सैन्यीकरण, युद्ध की मानसिकता, पर्यावरणीय आपदाओं, दूसरों से नफरत करने वाले राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरवाद और अति उपभोक्तावाद से मुक्त नई दुनिया बनाने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई है। इन दिनों, हमारे पास भरमार है ऐसे विशेषज्ञों की जो अंतरात्मा विहीन हैं, तकनीक की जो आत्मा से रहित है, बाजार जो नैतिकता मूल्यों से विहीन है, और मानव संसाधन जिसमें समृद्ध अंतःकरण और उच्च आदर्श नदारद हैं। शिक्षा का मौजूदा प्रचलित तरीका, शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को बेलगाम योद्धा में तबदील कर रहा है, यह स्थिति आगे ऐसी पीढ़ी बना रही है जो आनंद-विहीन एवं आक्रामक है, जिसको जरा चैन नहीं, जिसपर भय, मनोवैज्ञानिक संत्रास और आध्यात्मिक मूर्खता तारी है।

हां, यही मनोव्यथा आलोचना करने को उकसाती है। सफलता का पैमाना बना दी गईं नीट, जेईई, नेट और क्युएट जैसी परीक्षाओं की आलोचनाद् इम्तिहान जो हमारे विद्यार्थियों का आनंद, विचारशीलता, आत्मबोध, सहजता से सीखना जैसी नैसर्गिकता छीन रहे हैं। 'कोटा एकेडमी संस्कृति' का निंदक होना बनता है, राजस्थान का यह शहर जीवन लीलने वाला कोचिंग-उद्योग या किशोर जीवनकाल के जादुई वर्ष छीनने वाली मशीनों का पर्याय बन गया है और उन्हें 'परीक्षा योद्धा' सरीखे रोबोट्स में परिवर्तित कर रहा है, जिन्हें केवल एक ही चीज़ पता हैद्द भौतिकी या गणित के सवालों को कैसे जल्द से जल्द अथवा तत्काल हल करना है। गुस्सा आता है, उच्च शिक्षा का कॉर्पोरेटीकरण करने पर या शिक्षा का रुतबा 'प्राप्त सैलरी पैकेज' से मापने के भौंडे तरीके पर। और हां, कला एवं मानविकी को हेय गिने जाने पर चिंता उपजती है।

इस संदर्भ में, शिक्षा के भुला दिए कुछ आदर्शों की याद आना समीचीन है। मसलन, संवेदनशीलता, जिस पर जिद्‌दू कृष्णमूर्ति बारम्बार जोर देते थे, वह जो बौद्धिकता का उच्चतम स्वरूप हैद्द संवेदनशीलता जिंदगी के प्रति या प्रकृति के लिए। कृष्णमूर्ति युवा छात्रों को प्रेरित किया करते थे कि वे सूरज डूबने के विस्मयकारी दृश्य को पूर्ण चेतनता और समाधिस्थ अवस्था से निहारें। यह दिवास्वप्न देखने वाला निठल्लापन नहीं है, न ही समय की बर्बादी, यह भौतिकी और गणित से अल्पकालिक निजात भी नहीं है, इसकी बजाय यह सजग बनने, जागृत बौद्धिकता विकसित करने और उस स्वः को पोषित करने के लिए है, जो दुनिया से खुद का जुड़ाव बनाए। एक तरह से, यह शिक्षा का बोधात्मक, आध्यात्मिक पहलू है जो रबिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महज विद्यार्थियों की फौज खड़ी करने और दमनकारी शिक्षा संस्कृति की आलोचना में झलकता है और उनकी चाहत थी कि शिक्षार्थी युवाओं में कलात्मकता, सौंदर्यबोध का विकास हो। देवी प्रसाद के बारे में सोचेंद्द एक महान कलाकार और गांधी एवं टैगोर के शिष्य! अंतर्दृष्टि जागृत करने वाली उनकी लिखी किताब 'आर्ट- द बेसिस ऑफ एजुकेशन' मुझे बच्चे में अंदरूनी सृजनशीलता पैदा करने की जरूरत की याद दिलाती है। जरा उस नुकसान की तीव्रता के बारे में सोचें, जो हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को पहुंचाते हैं, जब हम उन्हें अंतस से जुड़ने का खूबसूरत बोध विकसित करने से महरूम करते हैं। तब वे भय, तनाव और अति-प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ बड़े होते हैं।

ऐसे में अक्सर अमेरिकी नारीवादी विदुषी बेल हुक्स से प्रेरणा मिलती है। जबतक वे जीवित रहीं, वे अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक शिक्षण एवं दूसरों का ख्याल रखने की नैतिकता के खूबसूरत मिश्रण से प्रेरित करती रहीं। पाअलो फ्रेरे, इरिक फ्रॉम और थिच हाट हान से हुए शैक्षणिक संवाद उन्हें नस्लवाद, पुरुष वर्चस्व और तमाम किस्म के दबदबों से सवाल करने की मजबूती प्रदान करते थे। और शिक्षा, जैसा कि उन्होंने अपने पढ़ाने और लिखने के ढंग से दर्शाया, वह है जो प्रेम की क्षमता पैदा करे और हिंसा से त्रस्त संसार के जख्मों पर मरहम लगाए। लेकिन फिर हमारे सामूहिक ह्रास और अधोपतन पर नज़र डालें। बतौर अभिभावक एवं शिक्षक, हम अपनी इस पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं यानी 'मोटी पगार'। हम उन्हें पागल घोड़े की तरह भागने और दूसरों के बारे में न सोचने को कह रहे हैंद्द जिसमें उनकी पीड़ा, संत्रास और मुश्किलें शामिल हैं। जिसे हम इन दिनों 'शिक्षा' मान रहे हैं, कदाचित्‌ केवल हिंसात्मक, श्रेणीबद्ध, शोषणकारी समाज के विचार को फिर से जीवित कर रही है।

अविजित पाठक

और अंत में, ख्यात राजनीतिक सिद्धांतकर्ता एवं दार्शनिक मार्था नुशबॉम का कथन दोहराया जाये- 'हर चीज़ लाभ कमाने के वास्ते नहीं होती, लोकतंत्र को मानवीयता की आवश्यकता है'। हम अपने कॉलेज-यूनिवर्सिटियों को मुख्यतः तकनीकी-वैज्ञानिक-अर्थशास्त्र पढ़ाने के स्थल की तरह देखते हैं और परिणामवश कला एवं मानवशास्त्र का अवमूल्यन हो रहा है। जैसे कि नुशबॉम की दलील है, यह वह सोच है जिसमें शिक्षा का मुख्य ध्येय छात्रों को आर्थिक रूप से उत्पादक होना सिखाना है, न कि आलोचनात्मक रूप से सोचने वाला, ज्ञानवान, उत्पादक किंतु सहृदय प्राणी बनाना। नुशबॉम का कहना है, 'मुनाफादायक कौशल' पर इस प्रकार एकतरफा ध्यान से वंचितों के प्रति सहानुभूति और आलोचनात्मक समझ बनने की क्षमता का ह्रास हो रहा है। शिक्षा को महज कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करने का औजार बनाने से परे देखते हुए, नुशबॉम शिक्षा को मानवीयता से जोड़ना चाहती हैं ताकि विद्यार्थी असल मायने में लोकतांत्रिक नागरिक बनने को प्रोत्साहित हों।

वाकई यही वक्त है, शिक्षा का असल अर्थ क्या है, इस बारे में पुनर्विचार करने का। यदि शिक्षा को घोर बाजारीकरण, तकनीकी-मशीनी तार्किकता और अस्तित्व के लिए खतरा बनी होड़ के वायरस से न बचाया, तो हम नई पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा बैठेंगे। इस अपराध के लिए हमें कतई माफी नहीं मिल पाएगी।

रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से क्षेत्रीय संतुलन

के.एस. तोमर

वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को वित्तीय संकट में डाल दिया था। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से 65 अरब डॉलर के लगभग तेल आयात किया जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इस निर्णय के पीछे एक सामर्थ्यपूर्ण कारण यह रहा कि भारत ने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से बचने का प्रयास किया। इस तरह के गठबंधन और व्यापारिक संबंधों के माध्यम से भारत ने रूस को अपने वित्तीय संकट से उभारने में मदद की।

यद्यपि भारत और अमेरिका के मध्य संबंध काफी सौहार्दपूर्ण रहे हैं लेकिन रूस से तेल आयात के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। इस बीच, अमेरिका को कमतर दिखाने के लिए चीन और रूस ने अत्यंत प्रभावी संबंध बना लिए थे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू प्रदान करके रूस ने भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को नई गति प्रदान की है। नौ जुलाई को क्रेमलिन में सम्मान प्रदान करते हुए दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करने के मोदी के प्रयासों की भी सराहना की गई।

अमेरिका द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत अपना रुख स्पष्ट करे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार यूक्रेन की संप्रभुता को बनाए रखने की सभी की जिम्मेवारी है। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि सभी देशों का दायित्व है कि रूस की आक्रामक नीति और यूक्रेन की जमीन से हमलावरों को खदेड़ने में भारत उसका साथ दे और शांति के लिए पहल करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिस्थितियों में मोदी की मॉस्को यात्रा को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। सभी एकमत हैं कि भारत जहां एक ओर चीन का प्रभाव कम करने में सफल रहा, वहीं आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी फायदे में रहा है। भारत की नीति ही चीन के विश्वस्तर पर बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में सक्षम है। रूस के साथ पुराने संबंधों को नई दिशा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी पहल की है। इस यात्रा का सबसे अहम उद्देश्य यह रहा कि चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियों के मुकाबले ऐसी व्यवस्था को बल दिया जाये, जिससे आपसी हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार के संबंधों से चीन या अन्य किसी भी राष्ट्र द्वारा आधिपत्य की कुचेष्टा को रोका जा सकेगा।

मोदी की मॉस्को यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत और रूस के रक्षा संबंधों को नई ताकत देना था। रूस भारत के सामरिक संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद सहयोगी रहा है। जहां इन संबंधों को लेकर इस दिशा में अच्छी पहल हुई, वहीं एस 400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली और भविष्य में सामरिक सुरक्षा तकनीक में सहयोग पर भी चर्चा हुई। इन संबंधों का सीधा लाभ भारत की युद्धशक्ति में बढ़ोतरी के अलावा दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन बनाए में होगा।

भारत और रूस के संबंधों में ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अपार तेल और गैस भंडारों के कारण रूस का अपना महत्व है जो भारत के दृष्टिकोण से अहम है। मोदी की इस यात्रा के दौरान लंबी अवधि के लिए सप्लाई के समझौते और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भी वार्ता का हिस्सा रहा। इन समझौतों का यह लाभ होगा कि भारत को भविष्य में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिससे देश का आर्थिक विकास तेज होगा।

रूस के साथ आपसी बातचीत में प्रधानमंत्री का ध्यान व्यापार को सुदृढ़ करने और पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी विशेष था। इस यात्रा का उद्देश्य था कि ऐसे नये क्षेत्र तलाशे जाएं ताकि व्यापारिक संबंध और बढ़ें। इनमें दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में व्यापारिक संबंधों को सुधारने और विभिन्न स्तरों पर पेश आ रही रुकावटों को दूर करने पर भी चर्चा हुई ताकि निवेश बढ़े और इसका लाभ दोनों देशों को मिल सके।

आज के उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद रूस के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना था। आज जब अमेरिका और पश्चिमी देश अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों की अनदेखी करके उन पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास कर रहे हैं, रूस से संबंधों में सुधार भारत की विदेश नीति में नया संतुलन लायेगा। रूस के साथ नए सुधरे हुए संबंध अन्य देशों को यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और बहुआयामी है।

इस यात्रा का यह भी लाभ रहा कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संस्थान जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत और रूस एक-दूसरे के सहयोग के कारण अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगे जिससे विश्व के देशों में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा।

भारत-रूस के बीच परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग रहा है। इन क्षेत्रों में और अधिक भागीदारी और सहयोग भी चर्चा का विषय रहा। आज के विश्व में डिजिटल आर्थिक व्यवस्था और साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मोदी की इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई ताकि दोनों देशों को लाभ मिले।

ऐसे में मोदी की मॉस्को यात्रा को भारत के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल माना जा सकता है। इस दौरान अनेक अहम मुद्दों पर न केवल चर्चा हुई बल्कि भविष्य के लिए मानचित्र भी तैयार किया गया। रणनीतिक तौर पर चीन के मुकाबले खड़ा होने और भारत की भूमिका अहम बनाने पर विस्तृत बातचीत हुई। इसके साथ ही पुराने संबंधों को सुदृढ़ करने और नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में नए समझौते लाभदायक रहेंगे।

बजट का हलुआ और हलुए का बजट

भारत अनोखा देश है। यहां सब कुछ अनोखा होता है ,जो दुनिया के शायद तमाम देशों में न होता हो। भारत में सरकार बजट पेश करने से पहले एक समारोह करती है जिसे अंग्रेजी में हलुवा सेरेमनी कहते हैं। इस हलुवा समारोह का लिखित इतिहास मुहे तो खोजने पर नहीं मिला,लेकिन जाहिर है कि इसके पीछे भी कांग्रेस ही रही होगी ,क्योंकि आज का भारत तो 2014 के बाद का भारत है। आज के भारत में स्टेशनों,शहरों और कानूनों के नाम बदले गए लेकिन गनीमत है कि इस हलुवा सेरेमनी को अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है।

भारत में हलुवा और बजट आम आदमी के लिए ही बनाया जाता है। हलुवा सबसे सस्ता और सुलभ मिष्ठान भी है। गांवों से लेकर शहरों तक लोकप्रिय है। अमीर-गरीब सभी इस हलुए को पसंद करते हैं। शायद अंग्रेज भी करते हों। हलुवे की लोकप्रियता कालांतर में इतनी बढ़ी कि इसे मुहावरे का सम्मान मिल गया। किसी भी काम में व्यापक पैमाने पर भ्र्ष्टाचार या गोलमाल करने को भी हलुवा करना ही कहा जाता है। हलुवा बनाना और हलुवा करना एक ख़ास कला है ,इस्सके कलाकार ज्यादातर सियासत में या नौकरशाही में मिलते हैं। जहाँ ईमानदारी से हलुवा बनता है वो जगह केवल गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारों में बनने वाले हलुवे को हलुवा नहीं कड़ा-प्रसाद कहा जाता है। हलुवा जब प्रसाद बन जाता है तो आत्मा को सुकून देता है, लेकिन जब हलुवा बजट बनता है तो हमेशा मीठा नहीं लगता।

वैसे आपको बता दूँ कि हलुआ एक प्रकार का मिष्ठान्न है जिसकी उत्पत्ति फ़ारस से हुई है और व्यापक रूप से पूरे मध्य पूर्व में फैली हुई है।। हलुवा साधारणतः आटे, सूजी, गहि और शर्करा से बनता है। बाद में आप इसमें बारीक पिसे हुए बीज या बादाम भी मिला सकते हैं आजकल तो हर चीज का हलुवा बननी लगा है जो बजट हलुवे से सर्वथा भिन्न होता है। हलुवा अब हैसियत से बाबस्ता हो गया है। जिसकी जैसी हैसियत उसका वैसा हलुवा। मठ का अलग,मंदिर का अलग और कर्तव्यपथ का लग किस्म का हलुवा होता है। मुंबई वालों का हलुवा तो सबसे अलग होता ही है। भाई अनंत की शादी में किस तरह का हलुवा बना हमें पता नहीं।

इस साल के बजट का हलुवा समारोह नार्थ ब्लाक में सम्पन्न हो गया। आम बजट के हलुवे को किसने बनाया मुझे नहीं पता, किन्तु केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले ये बजट हलुवा अपने मंत्रालय के अधिकारीयों और कर्मचारियों में तकसीम किया। इसी नार्थ ब्लाक में बजट छपने वाली छपाई मशीन लगी है। ताकि बजट लीक न हो। बजट लीक हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बजट में हलुवे की जो मिठास है वो आम आदमी तक भी पहुँच पायेगी या नहीं? देश में कांग्रेस ने दशकों तक बजट का हलुवा किया। अब एक दशक से भाजपा ये काम कर रही है। इस साल के बजट में तो भाजपा के साथ टीडीपी और जेडीयू को भी हलुवा करने का सौभाग्य मिला है।

कोई भी सरकार हो बजट में हलुवा करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की बजट में हलुवा करती ही है। ये बात और है कि अनेक राज्यों में हलुवा सेरेमनी नहीं होती। निर्मला जी मुझसे चार महीने छोटी हैं लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। निर्मला जी के पास हलुवा बनाने की कोई उपाधि नहीं है किन्तु उन्होंने भाजपा सरकार के लिए सबसे ज्यादा बार बजट हलुवा तैयार किया। वे राजनीति में पिछले दरवाजे से (राज्य सभा) आयीं थीं लेकिन वे पिछले छह -सात मर्तबा बजट हलुवा बनाने का सौभाग्य हासिल कर चुकी हैं। वे भाजपा की सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वित्त मंत्री हैं। उनके हलुवा बनाने पर किसी को संदेह नहीं हैसिवाय उनके अपने पति को। भाजपा सरकार ने बीच में उन्हें हलुवा बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देश कोई रक्षा का और बाद में कारपोरेट का काम भी सौंपा लेकिन जब दूसरे वित्त मंत्री ढंग से बजट हलुवा नहीं बना पाए तो उन्हें वापस वित्त मंत्री बनाकर बजट हलुवा बनाने की जिम्मेदारी दे दी गयी।

देश में किसी भी दल की सरकार हो लेकिन आम जनता को उसके बजट हलुवे से तमाम उम्मीदें बनी रहतीं है। इस बार के बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आगामी बजट को लेकर आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें सरकार की तरफ से थोड़ी राहत दी जाएगी। चूंकि यह बजट आम चुनावों के बाद का पहला बजट है ऐसे में सरकार के लिए भी यह बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

आम चुनाव में सरकार ले-देकर बनी है। इसलिए सरकार पर बजट को मीठा बनाने का दबाव है। सरकार के सामने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है। इस कारण सरकार द्वारा अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए आम बजट में लोगों को खुश को लेकर ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है।

नौकरीपेशा यानी सैलरी क्लास से लेकर, महिलाएं, किसान, टैक्सपेयर्स और युवावर्ग तक के लोग इस बार के बजट में सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे है। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट 2024 -25 पेश करेंगी तो उनके लिए कोई खास ऐलान किया जा सकता है। बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। तब तक सभी को बजट हलुवे की महक से ही काम चलना पडेगा। बजट हलुवे का स्वाद कैसा होगा ये 23 जुलाई को ही पता चलेगा।

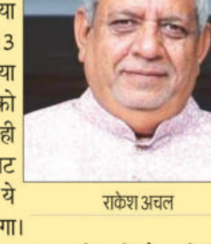

राकेश अचल

भाजपा सरकार का नया बजट स्वाद में चाहे जैसा हो किन्तु उसका रंग तो भगवा ही रहने वाला है। देश का भगवाकरण हो रहा है तो बजट और उसका हलुवा इस रंग से कैसे बच सकता है।

इस समय देश को ऐसे हलुवे की जरूरत है जो किसानोन्मुखी हो। किसान हलुवा पेश होने की फ़िक्र किये बिना अपनी पुरानी मांगों को लेकर छह महीने का राशन -पानी लेकर दिल्ली आने वाले है। इस बार सरकार उन्हें दिल्ली आने से रोक भी नहीं सकती, क्योंकि माननीय अदालत ने किसानों के दिल्ली जाने के अधिकार को संवैधानिक बता दिया है। अब देखना ये है की आने वाले दिनों में केंद्र द्वारा बनाया गया हलुवा फ़ैल तो नहीं जाएगा? भगवान करे कि ऐसा न हो।

असुरक्षित एक्सप्रेस-वे, पथराव में कई वाहनों के कांच फूटे, एक घायल

माही की गूंज, रतलाम।

मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (एटलेन) पर करीब 2.25 रुपये प्रति किमी का टौल टैक्स चुकाने के बाद भी सफर सुरक्षित नहीं है। प्रतिबंधित होने के बाद भी टू व्हीलर, ट्रैक्टर-ट्राली एक्सप्रेस वे पर चल रही है। इससे हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे से निकलने वाले वाहनों पर पथराव भी आम हो चला है। औसतन हर दूसरे-तीसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शनिवार-रविवार रात फिर से पथराव हुआ, इसमें कई वाहनों के कांच टूट गए व एक व्यक्ति घायल भी हुआ है।

जानकारी के अनुसार रात में बारह से एक बजे के बीच वाहन तेजी से एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे थे। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बायड़ी के समीप बदमाशों ने 10-12 वाहनों पर पथराव किया। इससे एक ट्रॉला व पांच कारों तथा अन्य वाहनों के कांच टूट गए। एक वाहन में सवार 35 वर्षीय जितेंद्र पाटीदार निवासी ग्राम अमलेटा घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

पथराव की जानकारी अन्य वाहन चालकों को लगी तो उन्होंने बायड़ी के पहले ही अपने वाहन रोक दिए। जिन लोगों के वाहनों के कांच टूटे थे वे सभी एकत्र हुए और पुलिस व एटलेन संबंधी एजेंसी को सूचना दी। इसके साथ ही धामनोद टोल नाके पर पहुंचकर भी जानकारी दी गई। शिवगढ़ थाने से पुलिस अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग कर पथराव करने वालों की खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस के अनुसार जितेंद्र पाटीदार की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

पूर्व विधायक के वाहन पर भी हो चुका है पथराव

एटलेन हाईवे पर चार-पांच पहले रावटी थाना क्षेत्र के पास माही नदी की पुलिया व झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र में रात के समय कई बार वाहनों पर पथराव करने की घटनाएं हुई थी।

एक फरवरी 2024 की रात भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना झाबुआ जिले के मेघनगर से रतलाम आ रहे थे। माही नदी की पुलिया के पास सड़क किनारे से अज्ञात लोगों ने उनके स्कार्पियों वाहन पर पथराव कर दिया था। इससे वाहन के आगे का कांच टूट गया था। वाहन चालक तेजी से वहां से वाहन निकालकर लाया था। जावरा के भाजपा नेता प्रदीप चौधरी की कार पर भी पथराव हुआ था। इसके अलावा कई वाहनों पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं।

निर्माण कंपनी के लिखित आश्वासन पर फोर लेन का धरना हुआ समाप्त

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के शामगढ़ में निर्माणाधीन उज्जैन गरोठ फोर लेन सड़क पर शामगढ नगर की कनेक्टिविटी की मांग के लिए चल रहा धरना प्रदर्शन दो दिन बाद समाप्त हो गया। सड़क निर्माण कर रही एमकेसी कंपनी के अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि जिस जगह से कनेक्टिविटी की मांग की जा रही है। उस हिस्से में अगले 30 दिनों तक कंपनी कोई निर्माण नहीं करेगी। इसके बाद धरना प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने धरने को समाप्त कर दिया।

गौरतलब है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से उज्जैन गरोठ फोर लेन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क मार्ग पर शामगढ नगर को नही जोड़ा गया है। नगर वासियों के कहना है कि नगर की 40 हजार से ज्यादा आबादी है। सभी ट्रेनों का स्टॉपेज है। आसपास के करीब 80 गांवों के लिए शामगढ सेंटर है इसके बाद भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शामगढ को कनेक्टिविटी नहीं दी गई। अब फोर-लेन हाईवे पर भी शामगढ को कनेक्टिविटी नही दी जा रही। इससे नाराज नगरवासियों ने रविवार से निर्माणाधीन फोरलेन हाईवे पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सोमवार को नगर बन्द रख विरोध दर्ज करवाया वही आज निर्माण कम्पनी के अधिकारियों ने 30 दिनों तक कनेक्टिविटी वाले हिस्से में निर्माण निर्माण कार्य नहीं करने का आश्वासन दिया है।

मंदिर परिसर में कोई वाहन खड़ा न हो, निर्धारित पार्किंग पर वाहन लगाए- कलेक्टर

माही की गूंज, मंदसौर।

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक पशुपतिनाथ सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि मंदिर परिसर में कोई भी वाहन खड़ा न किया जाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखे।

वाहन निश्चित पार्किंग पर ही खड़े हो इस बात को सुनिश्चित करें। पीडब्ल्यूडी विभाग मंदिर परिसर में बहुत अच्छे से बेरीगेटिंग करें।

उन्होंने कहा कि, श्रावण माह के दौरान पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य का काम अंदर से बंद रखें एवं बाहर कार्य लगातार चलने दे। पशुपतिनाथ लोक निर्माण एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करें। दर्शन करने आने वाले भक्त जनों को किसी प्रकार की चोट न लगे। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। नगर पालिका श्रावण माह के दौरान अधिक से अधिक संख्या में चलित शौचालय लगाए। होमगार्ड विभाग नदी के आसपास गोताखोरों को पर्याप्त मात्रा में तैनात करें।

कलेक्टर ने कहा कि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक टीम लगाए तथा 24 घंटे एंबुलेंस वहां रहे। मंदिर साफ सफाई व्यवस्था बेहतर हो इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। साफ-सफाई के दौरान काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही करें। कर्मचारियों के कार्य को देखकर उन्हें दैनिक वेतन प्रदान करें।

बैठक के पश्चात पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य, मंदिर परिसर एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर जो दुकान लगी हैं उनके बाहर जो सामग्री है उनको दुकानों के अंदर रखवाएं। निर्माण एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य डिजाइन अनुसार करें एवं कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ करें। कार्य में लापरवाही न करें। दीवारों पर जो डिजाइन के पत्थर लगाने है वह पत्थर उच्च गुणवत्ता के हो इस बात का विशेष ध्यान रखें।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, मंदसौर विधायक विपिन जैन, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल सहित अन्य सभी अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।

मंदिर में चोरी करने गए चोर को आ गई नींद, सुबह उठा तो बंधे मिले हाथ-पांव

माही की गूंज, शाजापुर।

माता-रानी के मंदिर में सामान चोरी करने के बाद अचानक चोर को नींद आ गई। सामान वहीं रखकर गर्भगृह में गद्दी बिछाकर चोर सो गया। सुबह श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे तो चोर सोता मिला।

लोगों ने चोरी करने आए युवक के हाथ-पैर बांधकर पुजारी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस चोर को पकड़कर थाने ले गई। हैरान करने वाला मामला शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लालबाई-फूलबाई की है। पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात को मंदिर का मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। मंदिर में चोरों ने कीमती सामान भी तलाशा, लेकिन चोरों को ज्यादा कुछ मिला नहीं। बाकी चोर तो भाग गए, लेकिन एक चोर को इतनी नींद आई कि वह माता-रानी के पास ही गद्दी डालकर सो गया। सुबह जब मंदिर में एक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे तो चोर सोया मिला। कोतवाली पुलिस को मंदिर पुजारी ने आवेदन दिया है।

तीन अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस

चोर से जब लोगों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सिलीगुड़ी का रहने वाला है। अपने तीन साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था। बाकी साथी चले गए, जबकि उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिन साथियों के साथ युवक चोरी करने आया था, पुलिस उनकी भी तलाश में जुट गई है।

चैतन्य टेक्नो स्कूल पर कलेक्टर ने लगाया 2 लाख का जुर्माना, मान्यता भी होगी रद्द

माही की गूंज, रतलाम।

जिला कलेक्टर ने डेलनपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही प्रशासन को स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा है। कलेक्टर ने ये कार्रवाई स्कूल परिसर से ही शिक्षण सामग्री बेचने मामले में की है। छापे में मिली शिक्षण सामग्री के बाद दिए गए नोटिस में स्कूल ने अपनी गलती स्वीकार की थी।

शिकायत के बाद छापे की कार्रवाई

प्रशासन को श्री चेतन्य टैक्नो स्कूल से ही सीधे किताबें, यूनिफार्म आदि बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इस पर सात जुलाई को प्रशासन के दल ने कार्रवाई की थी। इस दौरान शिक्षण सामग्री लेने आए कुछ अभिभावक भी वहां मिले थे। कार्रवाई के दौरान सामग्री बरामद करने के लिए प्रशासन दल को स्कूल भवन के कक्ष का ताला भी तोड़ना पड़ा था।

क्लासरूम में मिली थी ड्रेस, बेल्ट, टाई समेत स्कूली सामग्री

प्रशासनिक टीम ने स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के तीन कक्षों एवं प्रथम तल के एक कक्ष से 304 पैकेट बरामद किए थे। इन पैकेट में स्कूल ड्रेस, बेल्ट, टाई, मोजे, 295 पैकेट स्वेटर, कक्षा पहली से दसवीं तक की 366 बंडल किताबें, किताबों के नौ पैकेट, तीन कॉपी के बंडल थे। समस्त सामग्री सील करके जिला शिक्षा अधिकारी के सुपुर्द की गई थी।

नोटिस में स्कूल ने मानी है गलती

जिला शिक्षा अधिकारी से मिले प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 12 जुलाई तक जवाब मांगा था। जवाब में स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार की है।

मामले में कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि, जुर्माने की कार्रवाई अधिकतम सीमा तक की गई है, लेकिन स्कूल का कृत्य गंभीर है। इसलिए शासन को मान्यता समाप्त करने के लिए पत्र भी लिखा गया है।

चोरों के हौसले बुलंद, देवली बड़ा तालाब क्षैत्र से चुराई दर्जनों ट्यूबवैल मोटरों की केबल, ट्यूबवेल में गिराई मोटर

माही की गूंज, शुजालपुर।

बेख़ौफ चोरों ने पोलायकलां चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम देवली मैं खाटसुर मार्ग तालाब के नीचे वाली जमीन के किसानों की बीती रात को दर्जनों किसानों की ट्यूबवेल मोटरो की केवल काटकर मोटरों को बोरिंग मे गिरा कर रफुचक्कर हो गए। रात के अंधेरे में केवल को खींच वायरिंग निकाल ले गए। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, क्षेत्र में आए दिन चोरिया हो रही है। सोमवार बीती रात दस से बारह किसाने की ट्यूबवेल मोटरो की केवल अज्ञात चोरों ने निकाल ली। जिसकी सूचना हमें सुबह सात से आठ बजे हमारे खेत पर जाने के बाद लगी। हालांकि इस विषय में हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायती आवेदन संबंधित चौकी पोलाय कलां पर दिया है।

इस पूरे मामले में चौकी प्रभारी का कहना है कि, आसपास के क्षेत्र में कहीं दिनों से ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। हम पूरी कोशिश करते हुए इन अज्ञात व्यक्तियों को पड़कर उचित कार्यवाही करेंगे ऐसी घटना यदि घटित होती है तो आप हमें तुरंत सूचना करें या 100 डायल को सूचित करें एवं सभी किसानों को भी संगठित होकर संगठन के माध्यम से ऐसे गिरोह की निगरानी रखनी चाहिए।

विधानसभा में गुंजा अमालय-खमलाय मार्ग को जिला मार्ग घोषित करने मामला

माही की गूंज, शाजापुर। कालापीपल विधानसभा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी युद्ध स्तर पर काम करने लगे हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की सबसे खस्ता हाल सड़क का मुद्दा विधानसभा में सभापति के सामने रखा। उन्होने कहा जब ट्रैक्टर लेकर गांव से निकलते थे तो एक गाना याद आता था (मेरा मन डोले मेरा तन डोले) जब हम मोटरसाइकिल लेकर निकले हैं तो उड़े जब-जब उड़े जुल्फें तेरी,तो इतना परिवर्तन रोड़ों में आया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछ्ले 5 सालों में विकास नहीं हुआ, इस लिए रोड़ों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, 18-19 रोड हमारे क्षेत्र की है। उसमें से कुछ जिला मुख्य मार्ग भी है जैसे अमलाय-खमलाय कालापीपल मार्ग 3 मीटर का है जिस पर साल मे एक्सीडेंटो के कारण 19 मौत हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाए।

63 वर्ष मे पहली बार जिला अस्पताल में हुआ केंसर मरीज का ऑपरेशन

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर के जिला अस्पताल को बने 63 साल का समय पूरा हो गया। लेकिन अभी तक यहां मरीजों को कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का उच्च स्तरीय इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब यहां पर सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेज की खुद की बिल्डिंग नहीं होने की वजह से इसे जिला अस्पताल में मर्ज किया गया है।

सुंदरलाल पटवा चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से मेडिकल कॉलेज की सौगात मंदसौर वासियों को मिली है। इसे अभी चार साल तक जिला अस्पताल में संचालित किया जाएगा, जिसका लाभ यहां के मरीज को मिलेगा। मरीजों को अब बाहर रेफर नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में एक 80 वर्षीय महिला की जटिल कैंसर की सर्जरी की गई है। यह कैंसर मरीज की यहां की पहली सर्जरी है।

चार घंटे तक चला ऑपरेशन, छह साल से परेशान थी महिला

मेडिकल कॉलेज सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. ईशान चौरसिया ने बताया कि 80 साल की बुजुर्ग महिला पैर में गठान के समस्या के साथ आई थी। मरीज को यह समस्या पिछ्ले छह साल से थी। मरीज की एमआरआई जांच से यह पता चला कि मरीज को दाए पैर में सार्कोमा है, जो की हड्डियों और मांसपेशियों का दुर्लभ कैंसर है। इसके बाद महिला का ऑपरेशन करने की तैयारी की गई।डीन डॉ. शशि गांधी तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक एवं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. डीके शर्मा द्वारा तुरंत मरीज के ऑपरेशन के लिए लगने वाले सामान की व्यवस्था करवाई।

ऑपरेशन करने वाली टीम में सर्जरी विभाग के डॉ. ईशांत कुमार चौरसिया सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष तथा डॉ. अजय पाटीदार सहायक प्राध्यापक ने मरीज का जटिल ऑपरेशन किया। चार घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन के लिए बेहोशी विभाग के डॉ. डीके पिप्पल एवं डॉ. पीसी आर्य ने किया। ऑपरेशन के लिए मरीज की फिटनेस करवाने तथा ऑपरेशन के दौरान बेहोशी देने में बेहोशी विभाग के दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग तथा सर्जरी विभाग की मेहनत से मरीज 4-5 दिन में ही पूर्ण स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चल कर घर जा सकेगी।

470 बेड का है अस्पताल, इसी सत्र में शुरू होगी मेडिकल की पढ़ाई

गौरतलब है कि मंदसौर जिला अस्पताल 470 बिस्तरों का है। यहां पर लगभग सभी सुविधा उपलब्ध है। यही वजह है कि मेडिकल कॉलेज को इस अस्पताल के साथ मर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, इसी सत्र से यहां मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। पहले सत्र में 100 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहे हैं। तीन मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से एडमिशन भी किए जाएंगे। वहीं, दो मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से अभी उन्हें एडमिशन प्रक्रिया के लिए इंतजार करना होगा।

इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए निकला शहर में ताजियों का जुलूस

माही की गूंज, झाबुआ।

मुस्लिम समाज द्वारा मोहर्रम पर्व इमाम हुसैन की याद में पुर जोश तरीके से मनाया गया। इस्लामी केलेंडर के मुताबिक मोहर्रम माह की 9 और 10 तारीख को ताजियों का जुलुस निकाला गया। जुलूस में युवाओं ने या हुसैन का नारा बुलुंद करते हुए ताजिये उठाए। जुलूस में श्रद्धालुओं ने ताजियों की जियारत की और ताजियों के नीचे से भी निकले। श्रद्धालुओं ने ताजियों पर मन्ने मांगी और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया।

मोहर्रम माह की 10 तारीख यानि बुधवार को शहर के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हुड़ा और मारूति नगर से ताजिए उठाए गए जो जुलूस की शक ल में हुसैनी चौक, मौलाना आजाद मार्ग, पानी की टंकी से होते हुए राजवाड़ा चौक पर पहुंचे। यहां ताजियों को मुकाम दिया गया। यहां देर रात तक झिलमिलाती रोशनी में ताजियों का कारवां ठहरा रहा। शहर के राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में ताजियों को निहारने के लिए लोग उमड़े। चूंकि मोहर्रम पर्व सामाजिक, धार्मिक सद्भावना का प्रतिक है तो ताजियों के दर्शन के लिए शहर के सभी धर्म व समाज के लोग यहां पहुंचे। दर्शनार्थियों के लिए मुस्लिम समाज द्वारा जगह-जगह पानी व शरबत के स्टाल लगाए गए थे। कर्बला में इमामे हुसैन के काफिले पर दुश्मनों ने बड़े जुल्म किए और पीने के पानी तक पर रोक लगा दी गई थी। इसी के चलते मुस्लिम समाज द्वारा मोहर्रम पर पानी व शरबत का खूब वितरण किया जाता है। यह शरबत और पानी के स्टॉल हर एक आमजन के लिए खुले होते है यहां शरबत या पानी पिलाने में किसी का धर्म या जात नहीं देखी जाती। यह हर किसी के लिए होता है। जुलूस के पूरे रास्ते और राजवाड़ा चौक पर करीब दर्जन भर स्थानों पर इस तरह के शरबत के स्टॉल लगाए गए थे।

राजवाड़ा चौक पर जुलूस के पहुंचते ही यहां विभिन्न ताजियों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालु ताजियों को चूमते हुए मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने ताजियों पर बड़ी मात्रा में चिरोंजी, रेवड़ी तथा फूल चढ़ाकर अपनी आस्था जताई और मन्नते उतारी भी।

आधी रात के बाद ताजियों का यह जुलूस राजवाड़ा चौक से नेहरू मार्ग, सुभाष मार्ग, मेन बाजार होते हुए पुनः राजवाड़ा पर पहुंचा। जहां ताजियेदारों ने करबला से पानी लाकर ताजियों पर छीड़का। इसके बाद ताजियों को घर ले जाया गया। कुछ वर्षों पूर्व इन्ही ताजियों को बहादुर सागर तालाब में ठंडा कर दिया जाता था। मगर सरकार द्वारा जलाशयों में मुर्ति या ताजिया ठंडा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब से लेकर अब तक ताजियेदार ताजियों पर करबला के पानी के छीटें डालकर उन्हे वापस घर ले जाते है। पिछले बीते इन कई वर्षों में ताजियादारों के लिए को ठोंस वैकल्पिक व्यवस्था ताजिया ठंडे करने के लिए नहीं की गई। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी त्यौहारों पर मुर्तियां विसर्जित करने और ताजिये ठंडे करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अनास नदी के किनारे पोखर खोदकर की जाती रही है। मगर ताजियादारों के ताजिया ठंडा करने के लिए अलग स्थान दिए जाने की मांग वर्षों से चली आ रही है और अब भी यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। ताजिया ठंडा करने को लेकर ताजियेदारों का यह तर्क है कि अनास नदी पर प्रशासन द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था शहर से काफी दूर है। चूंकि ताजियों की साईज बड़ी होती है और इन में काफी वजन होता है, जिससे उन्हे अनास नदी तक ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है।

मोहर्रम के जुलूस में शामील हुई हिंदू मुस्लिम एकता

माही की गूंज, पेटलावद।

या हुसैन जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद..,मेरे मोला हुसैन है मेरे मोला हुसैन है, मोला अली-अली है, मोला अली-अली है,नाना भी बेमिसाल नवासा भी बेमिसाल...। बुधवार सुबह से देर रात तक या हुसैन के नारों से नगर की फिजा गूंज उठी। मौका था मोहर्रम पर चल समारोह का। इस आयोजन में विगत एक पखवाड़े से नगर के मुस्लिम व हिन्दु समाज के धर्मालंबियों द्वारा तैयार किए गए अपने ताजियों के जुलुस के लिए निकाले गए। प्रतिवर्ष की तरह ही इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज के लोगों ने ताजिए बनाए व नगर के प्रमुख मार्गों से घुमाते हुए करबला तक पहुंचाए। पेटलावद नगर में कुल 10 ताजियों का निर्माण हुआ, जिसमें कहार समाज से एक , आदिवासी समाज से एक तो मुस्लिम समाज ने 8 ताजियों का निर्माण किया। पेटलावद नगर में यह वर्षो की परंपरा हैं कि दोनों समुदाय मिलकर यह पर्व मनाते है। आपको बता दे कि यहां मोहर्रम का जुलुस सांम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतिक माना जाता है जिसमें मुस्लिम धर्मावलबीयों के साथ साथ हिंदू समाज भी शिरकत करता है। गौरतलब कि मोहर्रम पेटलावद तहसील में केवल मुख्यालय पर ही मनाया जाता है ओर आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में यहां आते है। देर रात तक नगर की सडकों पर ताजियों का जुलुस जारी था। जुलुस में ढोल नगाड़ों की थाप पूरे नगर को गुंजायमान कर रही थी तो ताजियों के जुलूस में कई लोगों ने अपनी मन्नते भी उतारी। सभी समाज के लोगों द्वारा छोटे बच्चों को ताजिये के नीचे से निकाला जाता है, इसके पीछे मान्यता यह हैं कि बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। मोर के पंखो की बुराक बनाई जो माहौल को सुगंधित कर रही थी। शहर में जुलूस का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। किसी ने दूध कोल्ड्रिंक

बनाया तो किसी ने पानी पिलाया ओर समाजजनों का स्वागत किया। इसके बाद शाम से लेकर रात तक किसी ने छबील पिलाई तो किसी ने पानी पिलाया। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए। स्थानीय पुलिस बल के अलावा बाहर से आई फोर्स को भी अलग-अलग जगह तैनात कर चाक-चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए। हुसैनी चौक के अलावा व्यस्तम क्षेत्रों में भी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय पुलिसकर्मी पूरे समय जुलूस की निगरानी में लगे रहे। समग्र मुस्लिम समाज ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों व समाजजनो का आभार माना।

मांगी मन्नते, चढ़ाई चिरोंजी

श्रद्धालुओं ने ताजियों को चूमते हुए उसके नीचे से निकले और मन्नतें मांगी। राजापुरा ईलाका लोबान की खुशबू से महक उठा। हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों ने चिरोंजी, रेवडी ले जाकर ताजियों पर फातेहा पढ़ी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी रात में कर्बला में ताजियो की जियारत की। राजापुरा, शनि मंदिर, झंडा बाजार, गणपति चौक, अंबिका चौक, सिर्वी मोहल्ला, होली चौक, महाकाल पथ, पुराना बस स्टैंड होते हुए वापस गणपति चौक, झंडा बाजार होते हुए करबला हुसैनी चौक पहुंचे।

केलीकला में लुट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश धराए, भेजा जेल

माही की गूंज,अमझेरा। विक्रमसिंह राठौर

अमझेरा थानांतर्गत 5 जून को ग्राम केलीकला और बलेड़ी के बीच दिनदहाड़े सुबह 10 बजे तीन अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाईकिल से रास्ता रोककर कलेक्शन एजेंट हरिसिंह पिता दिलीपसिंह ठाकुर निवासी ग्राम हिम्मतपुरा जिला सिहोर हालमुकाम राजगढ़ के साथ लुट की घटना को अंजाम देते हुए समुह लोन कलेक्शन की राशि 44 हजार रू. सहीत फिंगर प्रिंट डिवाईस व केश कलेक्शन शीट लुट कर फरार हो गये थे। जिसकी फरियादी के द्वारा अमझेरा थाने पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस जाच में जुटी थी। पुलिस गोपनीय सुचना तंत्र के आधार पर आरोपी कैलाश पिता कनसिंह परमार 32 वर्ष,दीपसिंह पिता सुभान परमार 19 वर्ष एवं कालु पिता सुभान परमार 27 वर्ष तीनो निवासी ग्राम धामाखेड़ी को पकड़ा एवं थाने लाकर सख्ती से पुछताछ करने पर तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। तथा आरोपीयों से लुट की राशि 44 हजार व फिंगर प्रिंट डिवाईस एवं केश कलेक्शन शीट को जप्त किया गया।

राजस्व विभाग के पोर्टल पर आदेश के अजब कारनामे डाल दिए 100 कोरे कागज

माही की गूंज,खरगोन।

कसरावद तहसील के प्रभारी तहसीलादर डा. मुन्ना अड़ ने राजस्व सिस्टम से बचने का नायाब तरीका निकाला है। तीन माह से ज्यादा समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण तो नहीं किया, लेकिन खुद के डिजिटल साइन किए हुए 100 से ज्यादा मामलो (नामांतरण, फौती नामांतरण, बिक्री बंटवारा) के आदेश की जगह कोरे कागज ही आरसीएमए (मप्र रेवन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन अपलोड आदेशों से मामलों का निराकरण हो गया है। इससे कलेक्टर कर्मवीर शर्मा व कमिश्नर दीपक सिंह की कार्रवाई से बचा जा सकता है। क्योंकि पोर्टल पर अपलोड आदेश(कोरे कागज) निराकरण की गिनती में आ जाएंगे। उधर, कोरे कागज अपलोड करने पर पोर्टल में अपलोड पर 1 नंबर दर्ज हुआ है। अब कुछ दिन में ही प्रभारी तहसीलदार मामलों का निराकरण कर देंगे और उनके निराकरण आदेश 2 नंबर से अपलोड कर देंगे। इससे लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी और प्रभारी तहसीलदार कार्रवाई से भी बच जाएंगे। तहसील कार्यालय में 400 से ज्यादा आवेदन लंबित पड़े हैं। इन आवेदकों का एक माह में निराकरण हो जाना था, लेकिन यहां तीन माह से ज्यादा का समय लगा दिया है। मामले में प्रभारी तहसीलदार डा. मुन्ना अड़ को अपनी कार्यशैली की भनक लगते हुए शनिवार को अवकाश के दिन ही बंद कमरे में मामलों का निराकरण के लिए काम किया गया।

पीड़ितों के काम तीन माह से लंबित है

धरमपुरा खड़गांव के संदीप देवेंद्रसिंह सोलंकी की जमीन बलगांव में हैं। उन्होंने 20 मार्च 2024 को क्रय-विक्रय आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया था। पोर्टल पर कोरा कागज का आदेश अपलोड हो गया है। इसी तरह खरगोन के दामोदर रामनारायण महाजन की जमीन कसरावद के सैलानी में हैं। 21 मार्च 2024 को क्रय विक्रय के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया है। खरगोन के अमन नगर के साजिद कलीम शेख की जमीन कसरावद के मुराबाद में हैं। इसमें 9 मार्च 2024 को क्रय विक्रय के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया था।कसरावद के गोपालपुरा के सालिगराम उर्फ सालकराम रतनलाल की जमीन ओझरा में है। नामांतरण के लिए 27 मार्च 2024 को आवेदन किया है। गुरुवार को सालिगराम के पुत्र रवींद्र जायसवाल, तहसील कार्यालय गए थे। यहां उन्हें रूम नंबर पांच में कहा कि, दोपहर दो बजे बाद आना। इसके बाद कुछ दिन बाद आने को कहा। उधर, बताया जाता है 12 जुलाई को कमिश्नर दीपक सिंह राजस्व विभाग की बैठक लेने वाले थे। इसके पहले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने 10 जुलाई को बैठक ली थी। कलेक्टर की बैठक के पहले ही प्रभारी तहसीलदार ने डिजिटल कागज अपलोड कर दिए। हालांकि कमिश्नर की बैठक 19 जुलाई को होगी।

सैकड़ों मामले लंबित

जिलेभर में नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारा आदि के हजारों मामले हैं। इन मामलों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। आवेदक, पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे है।

मामले की जानकारी लेते हैं

लोगों के मामलों के निराकरण आदेश आरसीएसएम पोर्टल पर डाले जाते हैं। यदि डिजिटल साइन के कोरे कागज अपलोड किए हैं तो ऐसा क्यों हुआ है।नायब तहसीलदार से पूरी जानकारी लेंगे।-दीपक सिंह, कमिश्नर इंदौर

कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस के निर्देश पर भड़के ओवैसी

नई दिल्ली। अगस्त से सावन महीने की शुरूआत हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगी हुई है। वहीं इस मुजफ्फनगर प्रशासन का एक निर्देश पर बवाल मचा हुआ है। इस निर्देश में कहा गया है कि, कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक और यहां काम करने वाले लोगों का नाम लिखना अनिवार्य है।

इस निर्देश के खिलाफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, जो अस्पृश्यता की बात करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है।दूसरी बात, जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, मुजफ्फरनगर की सभी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। क्या आप केवल एक समुदाय के लिए काम करेंगे? संविधान कहां है? मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि, अगर उनमें हिम्मत है तो वे लिखित आदेश जारी करें।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से ही रोगों से मुक्ति सम्भव

माही की गूंज,थांदला।

जिला स्वास्थ्य व आयुष विभाग के सहयोग से स्थानिय जैन समाज ने चातुर्मास प्रारम्भ होने से पूर्व स्वास्थ्य जागृति के लिए समाज में चल रहे वर्षीतप आराधकों तपस्वियों के साथ प्रत्येक सदस्य के लिए स्वास्थ्य परीक्षण व रोग निदान शिविर का आयोजन स्थानीय महावीर भवन पर किया। उक्त शिविर में स्वास्थ्य विभाग से महिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वाति मुजाल्दे, आयुष विभाग के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. बाबूसिंह राठौर, डॉ. जीवनलाल सोनी, डॉ. सुनीता खराड़ी, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉ. राकेश अवास्या, डॉ. नीलम चौहान आदि ने सेवाएँ प्रदान करते हुए 100 से अधिक सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें उचित परामर्श देते हुए निःशुल्क औषधि प्रदान की। शिविर में सभी सदस्यों का वेट, ब्लड प्रेशर व शुगर की जाँच सीएचओ अंकित झाला, शोभा मालिवाड़, नीलिमा डोडियार, ममता डामोर व हेमा पारगी ने की। वही आवश्यक औषधि कम्पाउंडर रमेशचन्द्र चौहान व गोविंद मकवाना ने दी। शिविर के बारें में जानकारी देते हुए संघ अध्यक्ष भरत भंसाली ने बताया कि, व्यक्ति को कर्मोदय से बीमारी आती है तो उसका शमन भी कर्माधिन ही है, लेकिन पुरुषार्थ तो हर जगह करना ही पड़ता है। उन्होंनें कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का मुख्य लक्ष्य बीमारी आने से पहले ही उसे जानकर समाप्त करना होता है। इसलिए सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहना चाहिए। संघ सचिव प्रदीप गादिया ने कहा कि जैन समाज में ज्यादा तपस्याएँ होती है ऐसे में उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर आयोजित किया जो सफल रहा व तप का प्रभाव भी देखने को मिला जिससे संघ में ज्यादा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नही दिखी। वरिष्ठ समाजसेवी नगीनलाल शाहजी ने भी सभी की आरोग्यता की कामना करते हुए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कि वकालत करते हुए कहा कि ऐसे शिविर से सभी को लाभ उठा कर अपने स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिये। शिविर संयोजक पवन नाहर ने जानकारी देते हुए कहा कि यह वर्ष प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्य श्री उमेशमुनिजी म.सा. ÷अणु÷ के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ऐसे में जैन समाज में 71 तपस्वी वर्षीतप की आराधना कर रहे है तो अनेक तपस्वी अन्य छोटी-बड़ी तपस्याएँ करते रहते है इस आराधना मय वर्ष में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर से भी जागृति आती है व व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त कर दीर्घ तपस्या के लिए अग्रसर होता है इसलिए स्वास्थ्य की तीनों महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति से सबका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की संघ सहमति संघ में ऊर्जा लाएगी वही इस वर्ष पूज्य अणुवत्स आदि ठाणा - 4 व पूज्याश्री निखिलशीलाजी आदि ठाणा - 4 के वर्षावास से चतुर्विद संघ में सिद्धितप आदि अनेक बड़ी तपस्या होने वाली है उसे भी गति मिलेगी। शिविर में संघ के वरिष्ठजनों के साथ महिलाओं ने भी परीक्षण करवाया। अंत में सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी डॉ. प्रमिला चौहान, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. भुवानसिंह डावर व डॉ रोहित मुजाल्दे के प्रति धन्यवाद ज्ञापति किया गया।

प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम पंचायत ने शुरू की अतिक्रमण हटाओ मुहिम

माही की गूंज खवासा।

ग्राम के व्यस्तमय मार्ग बाजना रोड और बस स्टैंड सहित बामनिया रोड पर अतिक्रमण की वजह से आए दिन यातायात में जाम की स्थितियां बन रही थी। कई वाहन चालकों के लिए इस जाम में कई बार अप्रिय स्थितियां भी बनी। जिसको देखते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत खवासा ने हाथ गाड़ी, थेला व सब्जियों की दुकानों के लिए स्थान चिन्हित कर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे। ग्राम पंचायत का कहना था कि, सभी दुकान एक जगह व्यवस्थित लगे और ग्राम में यातायात भी सुगम हो इसलिए छूटकर व्यापारियों को नोटिस के साथ समझाइस दी गई थी की वे शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण खाली करें। जिसकी समय सीमा भी निर्धारित की थी निर्धारित समय सीमा के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत गुरूवार को प्रशासनिक अमले के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा जहां उन्हें स्थानीय जनता के आक्रोश का भी कही-कही सामना करना पड़ा।

पूर्व में खुली भूमि पर हटाया था अतिक्रमण

इसके पूर्व में कुछ दिन पहले खवासा-बामनिया मार्ग पर खुली भूमि पर भी अतिक्रमण हटाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि, खवासा-बामनिया मार्ग पर खुली पड़ी शासकीय भूमि पर बाहरी व्यक्तियों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था और सीमाए चिन्हित कर उसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तथा उक्त अतिक्रमण पंचायत या प्रशासनिक अमले ने नही बल्कि स्थानिय लोगो ने ही हटवाया था जो प्रशासन को तमाचा भी था। तथा स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद इस भूमि को अतिक्रमण

मुक्त किया गया था। इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत सेमलिया में भी देखने में आया है। यहां पर भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से खेत के लिए तैयार कर दी थी। स्थानीय नागरिकों ने ही इसे भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और अब इस भूमि पर वृक्षारोपण करने की योजना ग्राम के नागरिक बना रहे हैं।

ठीक इसी प्रकार खवासा बामनिया मार्ग पर बड़े पैमाने पर पौधा रोपण कर एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया जा सकता है।

संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों के साथ बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का किया भ्रमण

श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक दर्शन हो,भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं किए जाने के दिए निर्देश

माही की गूंज, उज्जैन।

श्रावण भादौ मास और बाबा महाकाल की सवारियों की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त संजय गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का भ्रमण किया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

संभागायुक्त गुप्ता ने कहा कि, बाबा महाकाल की सवारी के श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके इसका ध्यान रखा जाए। सुनियोजित ढंग से भीड़ प्रबंधन किया जाए। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने वाली मंडलियों को पास जारी किया जाएं।

पुलिस महानिरीक्षक सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की सवारी मार्ग पर टू लेयर बेरिकेडिंग प्रभावी ढंग से की जाए। भगवान के मुखारविंद की पूजन के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। पुजन के दौरान पूर्व निर्धारित संख्या में ही पंडे, पुजारियों और अतिथियों को प्रवेश दिया जाए। बाबा महाकाल सवारी मार्ग में पड़ने वाले होटल संचालकों से भी चर्चा कर उनके चेकिंग और चेक आउट के समय पर परिवर्तन किया जाए।

बैठक के पश्चात संभागायुक्त गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक ने डीआईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर से महाकाल चौराहा, चौबीस खंभा, रामानुजकोट, रामघाट, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर होते पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे।

संभागायुक्त गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक सिंह ने उपरोक्त मार्गों पर बैरिकेडिंग समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग व्यवस्थित और मजबूत हो। एमपीईबी को निर्देशित किया गया कि बिजली के पोलो को प्लास्टिक शीट से कवर करवाएं। झूलते बिजली के तारों और खभों की मरम्मत भी की जाएं। एमपीईबी जगह-जगह अमले को तैनात करें। लोग ट्रांसफार्मर पर ना चढ़े, इसका विशेष ध्यान रखें। नगर निगम उज्जैन को सवारी मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, फायर ब्रिगेड सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर उज्जैन सिंह ने बताया कि, श्रावण भादौ मास में बाबा महाकाल की कुल 7 भव्य सवारियां निकाली जाएगी। जिसमें पहली सवारी 22 जुलाई को और अंतिम सवारी 2 सितंबर को निकाली जाएगी। बाबा महाकाल की सवारी अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थान कर समय पर पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैरिकेडिंग व्यवस्था और मरम्मत कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को पाबंद किया गया है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए एग्जिट गेट पर एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी। साथ ही बिस्तरीय अस्पताल का भी सुचारु संचालन किया जाएगा। सवारी मार्ग पर लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे। कलेक्टर सिंह ने बताया कि, इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए सवारी के साथ एक चलित रथ चलेगा जिसमें दोनों ओर एलईडी के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन हो सकेंगे।

इस दौरान डीआईजी नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत और प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर मृणाल मीणा, निगम आयुक्त आशीष पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौड़, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण संदीप सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

वर्षा की बेरुखी के कारण फसलों की वृद्धि रूकी कुछ खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए

किसानों को खाद बीज का हुआ नुक़सान

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में इस वर्ष मानसून विलंब से आने के कारण खरिब की फसलों की बुआई में भी देरी होने से खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए, जिस कारण कई किसानो को पुनः बुआई करना पड़ी। जिससे किसानो को खाद बीज का नुक़सान उठाना पड़ा है इधर वर्षा की खेंच के कारण फसलों की वृद्धि भी नहीं हो रही है।

गूंज संवाददाता के अनुसार क्षेत्र में मानसून विलंब से आने के कारण खेतों में बीज की बुआई में देरी होने तथा बाद में बारिश थम जाने के कारण बीज अंकुरित नहीं हुए जिस कारण पुनः बुवाई करना पड़ी। बीज अंकुरित भी हो गऐ मगर पुनः वर्षा की खेंच के कारण फसलों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जिसे देखकर किसानो को चिंता हो रही है तथा वे अच्छी वारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। कृषक राजेंद्रसिंह राठौर बोरझाड ने बताया कि, अपर्याप्त वर्षा के कारण खेतों में बोया गया सोयाबीन नहीं उगा जिस कारण पुनः बुवाई करना पड़ी।

एक अन्य कृषक कमलसिंह कनेश निवासी भोरदू ने बताया कि इस बार अभी तक जितनी बारिश हुई है। उससे फसलों का भविष्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा है।

बाग में देश का पहला यूनेस्को जियो पार्क, विज्ञानियों ने किया दौरा

माही की गूंज, धार।

धार जिले में स्थित डायनासोर की धरती पर नेशनल डायनासोर पार्क को यूनेस्को जियोपार्क के रूप में विकसित करने के लिए बुधवार को विशेषज्ञों ने दौरा किया। लखनऊ की बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियो साइंसेज के विज्ञानियों ने ईको टूरिज्म बोर्ड की सीईओ, कलेक्टर व मुख्य वन संरक्षक के साथ बाग क्षेत्र में जियो हेरिटेज से जुड़ी अलग-अलग साइटों को देखा।

विज्ञानियों ने भ्रमण की शुरुआत बाग गुफा से की

महाकालेश्वर मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर क्षेत्र में पहाड़ी पर स्थित लौह अयस्क की साइट पर गए। रायसिंगपुरा स्थित ज्वालामुखी लावे के उद्गम स्थल का दौरा किया। बता दें कि पूर्व में मुंबई और पुणे के पांच विज्ञानियों ने नमूने लेकर इस स्थल का अध्ययन किया था।

नमूनों से ज्वालामुखी लावा और जीवाश्म के अवधि काल को लेकर शोध किया गया। इसके पश्चात नीमखेड़ा स्थित जियो हेरिटेज की साइट का भ्रमण किया। नीमखेड़ा में छोटे-छोटे सफेद पत्थर के रूप मौजूद जीवाश्म को संरक्षित करने की बात कही गई है।

ग्राम पाड़लिया के नेशनल डायनासोर पार्क का भी विज्ञानियों ने भ्रमण किया। ज्ञात रहे कि देश में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नहीं है, जबकि दुनिया भर के 46 देशों में 195 यूनेस्को जियोपार्क हैं। अब भारत में पहला यूनेस्को पदनाम दिलाने के लिए धार जिले में गतिविधियां चल रही हैं। जियो पार्क की प्रक्रिया में मांडू, बाग के आसपास के वैश्विक महत्व की जगह को पर्यटकों के लिए जोड़ा जाएगा।

साइन बोर्ड लगाए जाएंगे

पर्यटकों को यहां लाने और आवश्यक सुविधाओं के साथ धरोहर को संरक्षित करने तथा साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. महेश ठक्कर, डॉ. शिल्पी शर्मा, ईको टूरिज्म बोर्ड की सीईओ डॉ. स्मिता राजौरा के साथ कलेक्टर प्रियंक मिश्र, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) नरेंद्र सनोड़िया, वनमंडलाधिकारी अशोक सोलंकी, बोर्ड मैनेजर अर्चना दास, जीवाश्म खोजी विशाल वर्मा, सहायक आयुक्त बृजकांत शुक्ला, डीएटीसीसी के नोडल प्रवीण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 दुर्दशा का शिकार

नए मार्ग बनाने की कवायद में पुराने की मरम्मत तक नहीं

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ ग्राम से बाहर की सीमा से होकर गुजर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 बिगत वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस मार्ग को डबल पट्टी मार्ग बनाया जाना है वह न जाने कब बनेगा इस नऐ बनाने के चक्कर में पुराने की मरम्मत तक नहीं हो रही हैं।

आम्बुआ से गुजरात सीमा सेजावाड़ा तक टूलेन सड़क मार्ग का निर्माण किया जना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 कई वर्षों से अपने उद्धार की राह देख रहा है हर बार अब बनेगा तब बनेगा की बातें होती रही हैं और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। विगत वर्ष मार्ग निर्माण की मंजूरी भी मिल गई मगर यह मार्ग आजाद नगर से होकर गुजर ने के कारण इसे बाहरी क्षेत्र (बायपास) से निकाला जाना है। जिसके लिऐ जमीन अधिग्रहण किया जाना था मगर किसानो ने जमीन देने से मना कर दिया तथा आंदोलन कर दिया जिसका कोई हल नहीं निकला नतीजा कार्य प्रारंभ नहीं हो सका और यह मार्ग आम्बुआ से सेजावाड़ा तक गड्ढे में तब्दील हो चुका है। रोड के दोनो किनारों मैं गहरे गहरे गड्ढे जोकि एकफीट तक गहरे हैं जिस कारण मार्ग पर क?ई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। क्षेत्रीय नागरिकों तथा वाहन चालकों की मांग है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। जब तक कार्य नहीं होता तब तक सड़क तथा किनारों की मरम्मत कराई जाए ताकि वर्षा काल में वाहन सुगमता से चल सके।

प्लास्टिक प्रोसेसिंग में जिले का नाम ऊपर, फिर भी उत्पाद जांचने के लिए नहीं है लेब

माही की गूंज, उज्जैन।

प्लास्टिक रिप्रोसेस उद्योग में उज्जैन की स्थिति मध्यप्रदेश में सर्वोच्च पायदान पर है, बावजूद यहां प्लास्टिक उत्पादों की जांच के लिए लैबोरेट्री नहीं है। उत्पादों की जांच कराने उद्यमियों को हमेशा की तरह अब भी भोपाल दौड़ना पड़ रहा है। क्योंकि वहीं के सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी में जांच की सुविधा है। उद्यमी उज्जैन में लैब खोलने के लिए कई बार आवाज उठा चुके हैं मगर सुनवाई आज तक न हुई। यही पीड़ा उज्जैन में तेजी से बढ़ रहे फूड और टेक्सटाइल उद्योग के उद्यमियों की भी है।

लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी अतीत अग्रवाल और राजेश गर्ग का कहना है कि उज्जैन में 70 से अधिक प्लास्टिक रिप्रोसेस उद्योग है। इतने ही पावरलूम संचालित है। प्लास्टिक और टेक्सटाइल उत्पादों की जांच के लिए कई बार लैबोरेट्री खुलवाने की मांग अफसरों से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री से की मगर मांग मंजूर न हुई।

विशेष बात ये है कि देवास रोड स्थित नागझिरी औद्योगिक क्षेत्र में खुले प्रदेश के पहले प्लॉस्टिक क्लस्टर कामन फेसिलिटी सेंटर की बकाया अनुदान राशि (लगभग दो करोड़ रुपये) भी दो साल से नहीं मिली है। नीमनवासा में प्लॉस्टिक इंडस्ट्री क्लस्टर खोलने को निविदा स्वीकृत होने के महीनों बाद भी केबिनेट से मंजूरी नहीं हुई है।

लघु उद्योग भारती की सरकार से मांग है कि लैब के साथ उज्जैन में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खुले। हमारा मानना है कि उम्दा उत्पाद बनाने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। उज्जैन में प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी तो रिप्रोसेस प्लास्टिक इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ेगी। पुराने अनुपयोगी प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने में ये कारगर कोशिश होगी।

नगर निगम की लापरवाही

उज्जैन नगर निगम के अधिकारी, निगम परिषद से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने को अपनी लैब नहीं बनवा पाए। अब भी निगम अपने निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की जांच के लिए गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब पर निर्भर है। इस जांच के एवज में निगम को हर साल लाखों रुपये इंजीनियरिंग कालेज को चुकाना पड़ते हैं। इससे कॉलेज की आय बढ़ रही है, मगर नगर निगम का घाटा भी।

विशेष बात ये है कि अरबों रुपये के काम कर रहा उज्जैन विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल सहित अन्य निर्माण एजेंसियां भी सड़क या बिल्डिंग मटेरियल की जांच कराने के लिए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज या उज्जैन पालीटेक्निक कॉलेज पर निर्भर है। मामले में महापौर मुकेश टटवाल ने पुराना स्वीकृत ठहराव निकलवाकर प्रस्ताव अमल में लाने की बात 'नईदुनिया' से कही है।

अजगर ने मुर्गी पकड़ी ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ा

माही की गूंज, आम्बुआ।

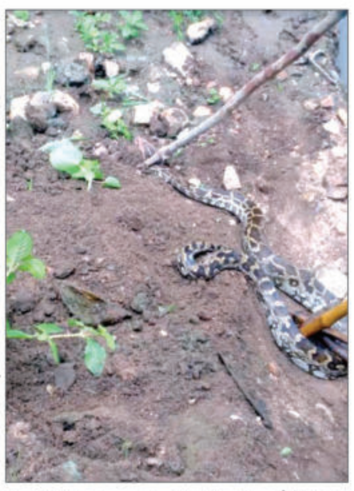

आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम भोरदू में नाले के समीप एक भारीभरकम अजगर आ धमकता तथा उसने घर के पास खेत में घूमरही एक मुर्गी को पकड़ लिया मुर्गी की आवाज सुन कर ग्रामीण दौड़े तथा मुर्गी को छुड़ाया तथा अजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ा।

हमारे संवाददाता को ग्राम भोरदू निवासी कमलसिंह कनेश ने बताया कि ग्राम की खोदराफलिया में नाले के पास एक बड़ा अजगर निकला तथा उसने एक मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी की आवाज सुन कर ग्रामीण दौड़े तथा मुर्गी को छुड़ाया तब तक मुर्गी मर चुकी थी। अजगर कोई बड़ा नुक्सान न करदे कुछ युवकों ने हिम्मत करके उसको पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर को पकड़ ने की हिम्मत करने वाले शेर सिंह, कुशलसिंह,अनील तथा मगन रावत की ग्रामीण प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये युवक हिम्मत नहीं करते तो भविष्य में वह कोई बड़ा नुक्सान कर सकता था।

ग्रामीण दृष्टिहीन पुनर्वास केंद्र का संयुक्त कलेक्टर ने किया निरीक्षण

माही की गूंज, अलीराजपुर। चंद्रशेखर आजाद आदिवासी ग्रामीण दृष्टिहीन पुनर्वास केंद्र चंद्रशेखर आजाद नगर का निरीक्षण संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रियांशी भवर द्वारा किया गया। यहां पर कुल 12 दृष्टिहीन बच्चों ब्रेल लिपि में अध्ययन करते हुए पाए गए, उपस्थित बच्चों द्वारा ब्रेल लिपि में पढते एव ब्रेल लिपि में लिखते हुए पाए गए हैं। रसोईया कक्ष का परीक्षण किया गया जिसमें दाल, चावल, मिर्ची पाउडर तथा आटा अच्छी गुणवत्ता में पाया गया किंतु रसोईया कक्ष मैं स्वच्छता का अभाव, रसोईया कक्ष तथा बच्चों के निवासरित कक्ष झज्जर स्थिति में पाए गए उक्त संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण संध्याकाल होने से दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा भजन गान किया गया। भजन गान उपरांत बच्चों को स्वल्पहार प्रदाय करते हुए संस्था को पुन संस्था को झज्जर भवन को रिपेयरिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

पीथमपुर-धार रेलवे ट्रेक ने रोकी पानी की राह, डूब गई फसल

माही की गूंज, धार।

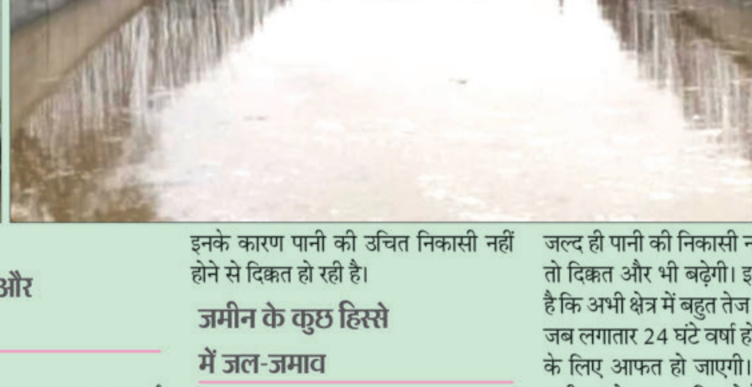

इंदौर से दाहोद के बीच निर्माणाधीन रेल परियोजना के तहत पीथमपुर से धार के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। इस खंड में रेलवे ट्रैक बनने से वर्षा के पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया। नतीजतन, पानी ट्रैक के आसपास वाले खेतों में जमा होने लगा है।

कई स्थानों पर खेत तालाब बन गए

पानी भरने से कई स्थानों पर खेत तालाब बन गए हैं। किसानों का आरोप है कि रेल परियोजना के तहत पानी निकासी का उचित इंतजाम नहीं किया गया है। इसी प्रकार अंडरपास और अन्य ब्रिज निर्माण के कारण भी धार जिले के गुणावद क्षेत्र में परेशानी बनी हुई है।

20 किसानों की 100 बीघा फसल प्रभावित

ग्राम एकलदुना, दिग्ठान व नजदीक के ग्रामों में करीब 20 किसानों की 100 बीघा फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की यह फसल जलमग्न हो गई है। गांव गुणावद के नजदीक नियामतखेड़ी में बन रहे अंडरपास में जल-जमाव से आवाजाही प्रभावित हुई है।

मुख्य कार्य धार और इंदौर के बीच

वर्तमान में परियोजना का मुख्य कार्य धार और इंदौर के बीच चल रहा है। करीब 60 किलोमीटर लंबे भाग में अलग-अलग स्थानों पर काम किया जा रहा है। परियोजना के बुनियादी निर्माण के चलते अर्थवर्क किया गया है। रेलवे ट्रैक तैयार करने के लिए मिट्टी और गिट्टी तथा स्लीपर रखे गए हैं। इनके कारण पानी की उचित निकासी नहीं होने से दिक्कत हो रही है।

जमीन के कुछ हिस्से में जल-जमाव

ग्राम एकलदुना के खेमराज पाटीदार ने बताया कि हमारी जमीन के कुछ हिस्से में जल-जमाव हो गया है। इससे नुकसान हो रहा है। रेलवे के ठेकेदार को गत वर्ष भी बताया गया था कि इस ओर ध्यान दिया जाए, फिर भी कार्य नहीं किया गया। कृषक नारायणा पाटीदार ने बताया कि पानी भरने से सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है।

फिर बढ़ जाएगी दिक्कत

रेलवे द्वारा जल्द ही पानी की निकासी नहीं की जाती है, तो दिक्कत और भी बढ़ेगी। इसकी वजह यह है कि अभी क्षेत्र में बहुत तेज वर्षा नहीं हुई है। जब लगातार 24 घंटे वर्षा होगी, तो किसानों के लिए आफत हो जाएगी। किसान पंकेश पाटीदार ने बताया कि खेतों में भरा पानी सोयाबीन की फसल को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ग्राम गुनाणद के निकट नियामतखेड़ी में अंडरपास में करीब पांच फीट तक पानी भर गया है। इसे निकालने के लिए रेलवे ने एक मोटर लगाई है, किंतु वह भी पानी खींचने में सक्षम नहीं है।

बेरहम सरकार...

अध्यक्ष, सीएमओ, कलेक्टर, मंत्री सब महिला, लेकिन 6 वर्षों से पट्टे के लिए परेशान पूनम

अतिक्रमण का दंश झेल रहा पूनम का परिवार, राष्ट्रपति तक लगी गुहार पर नही मिला न्याय

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

महिलाओं के नाम पर पक्ष-विपक्ष अपनी राजनीतिक चमका कर वोटों की फसल चमका रहे है, लेकिन धरातल पर स्थितिया इतनी दयनीय है कि, कहना पड़ रहा है ÷बेरहम सरकार÷। जहा स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यवस्था महिलाओं के जिम्मेदार कंधों पर है वही पर एक लड़की न्याय के लिए विगत 6 वर्षों से परिवार सहित भटक रही है। वर्ष 2019 में आई अतिक्रमण की एक मुहिम ने इस परिवार के अपने निजी घर के सपने तोड़ दिये। बदले में मिले बड़े-बड़े वादों के बाद एक अद्दत पट्टे के लिए परिवार परेशान हो रहा है।

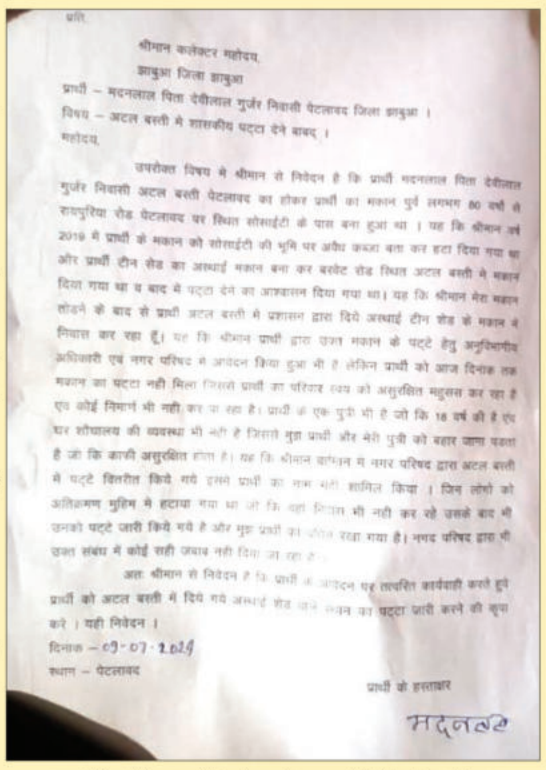
प्रति
श्रीमान कलेक्टर महोदय
झाबुआ जिला झाबुआ
प्रार्थी – मदनलाल पिता देवीलाल गुर्जर निवासी पेटलावद जिला झाबुआ।
विषय – अटल बस्ती मे शासकीय पट्टा देने बाबद।
महोदय,
दिनांक – 09-07-2024
स्थान – पेटलावद
प्रार्थी के हस्ताक्षर

पूनम के पिता देवीलाल गुर्जर ने कलेक्टर को जनसुनवाई में पट्टे हेतु दिया आवेदन।

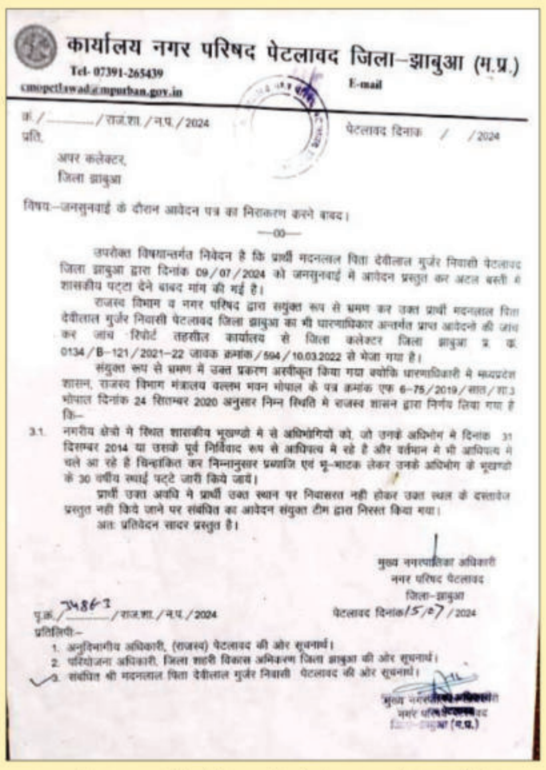
कार्यालय नगर परिषद पेटलावद जिला-झाबुआ (म.प्र.)
पेटलावद दिनांक 15/07/2024
प्रतिलिपि–
1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री मदनलाल पिता देवीलाल गुर्जर निवासी पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद पेटलावद
जिला-झाबुआ (म.प्र.)

नगर परिषद द्वारा पट्टा नही मिलने के कारण के उल्लेख के साथ दरवाजे पर चस्पा नोटिस।

पट्टे के अभाव में बिना सुविधा चद्दर पोश मकान में रहने पर मजबूर पूनम और उसका परिवार।

बिना शौचालय के टीन शेड में रहने पर मजबूर परिवार, पट्टा नहीं होने से सता रहा डर

लगभग 80 वर्षो से नगर के बीचों बीच स्थित बेशकीमती भूमि पर रह रहे देवीलाल गुर्जर और बेटी पूनम गुर्जर को 2019 में आई अतिक्रमण मुहिम के दौरान ये कह कर जबरन हटा दिया गया कि, जमीन सोसाइटी की है। मंशा साफ थी सरकार में बैठे लोगों की इस जमीन पर नियत खराब थी और शासन-प्रशासन का भरपूर उपयोग कर परिवार को बेघर कर दिया गया। साथ ही परिवार को गाँव से दूर मलिन बस्ती में नगर परिषद के द्वारा टीन शेड का मकान बना कर स्थापित किया गया और कहा गया कि जल्द ही पट्टा दिया जाएगा ताकि यहां निर्माण कार्य कर मकान बनाया जा सके। तब से परिवार बिना शौचालय वॉले टिन शेड़ मकान में रहने पर मजबूर है। लगातार 6 वर्षो से परिवार पट्टे के लिए ऑफिस-ऑफिस के चक्कर लगा रहा है लेकिन आज तक परिवार को न्याय नही मिला। अब परिवार को ये डर सता रहा है कि, 80 सालों से जिस जगह रह रहे थे अतिक्रमण के नाम से वहां से हटा दिया तो पट्टे के अभाव में किसी दिन ये छत भी छीन ली जाएगी।

सभी पदों पर महिलाएं फिर भी एक बेटी के दर्द को संजोने वाला कोई नहीं

पेटलावद नगर परिषद में अध्यक्ष और सीएमओ महिला है। वही जिले की कलेक्टर ओर क्षेत्र की विधायक व महिला बाल विकास मंत्री भी महिला है। बावजूद इसके एक बेटी के दर्द को समझ नही पा रहे है और एक स्थाई पट्टे के लिए भटकना पड़ रहा है। परिवार के साथ हुई ज्याददती को लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक भी गुहार लगाई गई लेकिन कोई निराकरण नही हुआ।

पूनम को छोड़ कई लोगों को मिला पट्टा

नगर परिषद द्वारा कई लोगो को नवीन पट्टा जारी किया जिसकी जानकारी मिलने पर पूनम के पिता देवीलाल गुर्जर ने नगर परिषद से उनके पट्टे की जानकारी चाही तो कोई जबाब नही मिला। जिसके बाद पूनम के पिता ने जनसुनवाई झाबुआ में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई । जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद सीएमओ को निराकरण करने को कहा गया। जिले से पूनम के परिवार को धारणा योजना में पट्टे के लिए ऑन लाइन आवेंदन करने के लिए साइड दी गई ।

पट्टे के लिए आवेदन नही होने का हवाला देकर नोटिस किया चस्पा

पट्टे के लिए भटक रहे परिवार को नगर परिषद से किसी प्रकार का सहयोग नही मिला। न ही धारणाधिकार योजना अंतर्गत पट्टे के लिए आवेदन की जानकारी दी गई। परिवार जानकारी के अभाव में एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्टर तक पट्टे की मांग करता आ रहा है लेकिन हर बार आवेदन बिना निराकरण के फाइलों में दब कर रह गये। इस बार कलेक्टर के निर्देश पर पट्टे के लिए नगर परिषद को कहा गया था, नगर परिषद की ओर से गुर्जर परिवार के दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिंसमे उल्लेख किया गया कि, आवेदक द्वारा धारणाधिकार योजना के तहत पट्टे के लिए आवेदन नही किया गया। पट्टे के लिए परेशान हो रहे परिवार की किसी ने भी मद्दत कर सही राह दिखाने ओर सहयोग करने की बजाए पट्टे के लिए किए गए आवेदन को शिकायत समझ कर बे-रहम व्यवहार किया जा रहा है।

एक इंच जमीन नहीं परिवार के पास

पूनम का परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से पेटलावद में निवास कर रहा है लेकिन सरकारी नियमों के विपरीत 80 साल एक जगह रहने के बाद भी परिवार को सरकारी नियमो के अनुसार पट्टा नही दिया गया। उल्टा उसे अतिक्रमण बता कर हटा कर मार्केट का निर्माण करवा दिया गया। परिवार अब टीन शेड से बने अस्थाई घर मे निवास कर रहा है और परिवार के पास मध्यप्रदेश में तो ठीक पूरे देश मे एक इंच जमीन का टुकड़ा नही है। वही अगर नगर में दिए गए पट्टों की सूची की जांच की जाए तो ऐसे कई मामले उजागर होंगे जिंसमे पट्टाधारक और उसके परिवार के पास पूर्व से मकान ओर जमीन मौजूद है। ऐसे में एक मासूम लड़की को रहने के लिए एक स्थाई छत की व्यवस्था के लिए एक मात्र पट्टे के लिए हर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे है जहां से परिवार को पट्टा मिलने की उम्मीद है पर यह उम्मीद कब पुरी होगी यह पता नही।

बैंकों में नकली सोना रख लिया जा सकता है लोन...? यह सिद्ध किया शातिर अरविंद नायक ने

मैनेजर की सांठ-गांठ के साथ बैंक गोल्ड वैल्यूवर ने बड़ी संख्या में अलग-अलग खातेदारों के नाम नकली सोना बैंक में रख लोन लेता रहा नायक

एक वर्ष से मामले में चल रही थी खानापुर्ति, नए मैनेजर की रिपोर्ट पर हुआ मामला उजागर

माही की गूंज, थांदला (झाबुआ)। मुकेश भट्ट

झाबुआ जिले में अपने शातिराना दिमाग के साथ लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्तियों की कमी है यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिले में शातिराना दिमाग के साथ कहीं फर्जी आरटीओ कर्मचारी बनकर, तो कहीं फर्जी पत्रकार, तो कहीं फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले सामने आए हैं। तो वहीं फर्जी स्कीमो के साथ भी लोगों के साथ ठगी की जाना आम बात हो चुकी है।

फर्जी स्कीम में ठगी की बात करें तो सारंगी का एक बड़ा मामला जिले में सामने आया था, जिसमें स्कीम संचालक अंतिम बसेर व उसका बड़ा भाई जितेंद्र बसेर के साथ 17 व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज हुआ था। वही दोनों भाई को जेल की हवा भी उक्त मामले में खानी पड़ी थी। एजेंट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ हुई बड़ी ठगी का पैसा 8 वर्ष बाद भी वे आज भी उक्त फर्जी स्कीम संचालक दोनों भाईयो से मांग रहे हैं। कहीं न कहीं भले ही मामले में न्यायालय प्रकिया से छुटकारा मिल गया हो पर यह मामला आज तक भी विवाद का कारण बना हुआ है। इसी तरह जिले में लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है।

हाल ही में 21 जून को बैंक मैनेजर की रिपोर्ट के बाद एक बड़ा मामला ठगी का सामने आया। जिसमें बैंक का गोल्ड वैल्यूवर ने अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से बैंक में बड़ी संख्या में खाते खुलवाकर नकली सोने का असली का मूल्यांकन कर स्वयं वैल्यूवर ही बैंक में मैनेजर की साठ-गांठ के साथ नकली सोना रखता और विभिन्न बैंक खातों से असली सोने का लोन प्राप्त करने का बड़ा मामला सामने आया। उक्त मामला झाबुआ जिले में थांदला स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का सामने आया है। जिसमें वर्तमान में पदस्थ थांदला मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक प्रवीण मरमट ने थांदला थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया गया कि, बैंक से गोल्ड लोन लेने हेतु सोने का मूल्यांकन हेतु बैंक की ओर से मूल्यांकनकर्ता होता है और उसी मूल्यांकनकर्ता अरविंद नायक ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर नकली सोना बैंक में रखवा कर असली मूल्यांकन कर करीब 81 खातेदारों के नाम से गोल्ड लोन लिया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थांदला थाने में धारा 420, 406, 468, 768, 471 में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले का मुख्य आरोपी अरविंद नायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

नकली सोना बैंक को दे-देकर ठगी करने वाला शातिर बदमाश अरविंद नायक।

वहीं बैंक के आला अधिकारियों ने बैंक की साख बचाने के लिए थांदला शाखा में पूर्व में पदस्थ रहे शाखा प्रबंधक बृजेश शिवहरे व अमर सिंह अहिरवार को निलंबित किया गया।

बताया जाता है कि, बैंक में गोल्ड लोन लेने हेतु दो वैल्यूवर रखे जाते हैं। पहले वैल्यूवर निर्धारित बैंक की लोन राशि पर गोल्ड का मूल्यांकन मान्य होता है तथा अधिकतम निर्धारित लोन राशि से अधिक राशि का गोल्ड लोन होने पर दूसरे वैल्यूवर का भी बैंक में सोने का मूल्यांकन का प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। शातिर अरविंद नायक के संबंध में बताया जा रहा है कि, पहले अरविंद नायक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में किसी परिचित अधिकारियों से संपर्क कर गोल्ड वैल्यूवर बनने हेतु तय हुआ। तथा उसके बाद नियोजित रूप से गोल्ड वैल्युवर बनने हेतु अरविंद नायक ने सोने चांदी का व्यापारी बनने का नाटक कर सोने चांदी क्रय-विक्रय की एक दुकान खोली तथा बैंक का गोल्ड वैल्यूवर बनने के बाद शातिर अरविंद नायक ने सोने-चांदी के क्रय-विक्रय की दुकान बंद कर दी। तथा सुनिमोजित तरीके से बैंक से ठगी करने हेतु गोल्ड वैल्यूवर अरविंद नायक ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता रहा जो उसके अधिन या परिचित हो। जिनके आवश्यक दस्तावेज लेकर कुछ लोगों को बैंक से सब्सिडी के नाम पर लोन लेने एवं कुछ को अरविंद नायक द्वारा ही बैंक में दूसरे खाताधारकों के नाम से सोना रख लोन लेने की बात कही। जिसमें अरविंद नायक परिचित लोगों को झांसे में लेकर यह विश्वास दिलाता था कि, लोन हेतु उसके स्वयं का सोना अमानत के रूप में बैंक में रखा हुआ है। तथा खातेदार के खाते में गोल्ड लोन के नाम से पैसा आने के बाद अरविंद नायक उक्त लोन राशि पूरी प्राप्त कर लेता था और खातेदारों को समझाता था कि मेरे द्वारा बैंक में उक्त लोन राशि भर दी जाएगी और अगर नहीं भरूंगा तो मेरा सोना ही बैंक में कट जाएगा।

चित-परिचित, अरविंद नायक की बातों में आ गए और मामले को सामान्य समझकर अरविंद नायक को अपने दस्तावेज दे दिए और अरविंद नायक ने एक दो नहीं बल्कि बैंक की अधिकतम निर्धारित लोन राशि जिसमें सोने का एक ही मूल्यांकन पर लोन नकली सोना रखकर 81 खातेदारों के नाम से बड़ी राशि आहरण लोन के नाम से फर्जी रूप से आहरण कर ली। वही अरविंद नायक पर विश्वास करने वाले उन अनजान व बेगुनाह चित-परिचित व्यक्ति जिनके खाते बैंक में खोले गए उन्हें भी आज बराबर का ठगी करने के मामलों में आरोपी बना दिया गया है।

बताया जा रहा है उक्त मामला बैंक में 1 वर्ष पूर्व ही उजागर हो चुका था और नगर में भी अंदर के अंदर बात फेल चुकी थी। वही बैंक में प्रतिवर्ष होने वाले ऑडिट के दौरान भी झोल हुआ है एक वर्ष से अधिक समय तक उक्त मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया। वहीं बैंक अधिकारियों का प्रयास रहा था कि, अरविंद नायक द्वारा विभिन्न खातेदारों के नाम से लिए गए करीब 3 करोड़ की राशि बैंक को भर दे लेकिन अरविंद नायक सिर्फ पांच खातों की राशि पूरी चुकता कर पाया। वहीं करीब तीन खाते की कुछ लोन राशि भरी गई। बाकी 73 खातों में कोई राशि जमा नहीं होने पर वर्तमान शाखा प्रबंधक किसी झमेले में नहीं पढ़ना चाहते थे इसलिए बैंक की और से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उक्त मामला उजागर हुआ।

उक्त मामले में अरविंद नायक के साथ वे शाखा प्रबंधक भी बराबर गुनेहगार है जिनके सहयोग के साथ यह पूरा मामला हुआ है। अतः निलंबन नहीं वरन उन मैनेजरो के नाम से अपराध दर्ज होकर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बैंक मैनेजर को प्रलोभन देकर इस तरह से फर्जी लोन नहीं ले सके। वरना अरविंद नायक ने तो बैंकों में नकली सोना रख लोन लिया जा सकता है का संदेश दे चुका है। नतीजन अरविंद नायक की तर्ज पर कई ऐसे शातिर बैठे हैं जो इस फार्मूले को अपनाकर बैंकों से जाल साजी करने का प्रयास जरुर कर सकते हैं...? इसलिए सजग रहे और सतर्क रहे।

शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे भ्रष्ट, अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भी भ्रष्टाचार की तैयारी

न तो कहीं विज्ञप्ति चस्पा हुई, न आवेदकों से आवेदन ले रहे ये कैसी चयन प्रक्रिया!

माही की गूंज, मेघनगर। इमरान शेख

एक कहावत है की एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। मगर भ्रष्ट है की किसी भी जगह को नही छोड़ना चाहते। ऐसा ही भ्रष्टाचार का खेल मेघनगर ब्लॉक के स्कूलों के प्राचार्य भी कर रहै है। सहायक आयुक्त जनजाति विभाग द्वारा 15 जुलाई को जनसंपर्क विभाग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी को प्राचार्यों के माध्यम से जिले की प्राथमिक से हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर 2024 के शिक्षण सत्र के लिए अतिथि शिक्षक वर्ग की 1,2 व वर्ग 3 के चयन हेतु आदेशित किया था। मगर जिम्मेदार अधिकारी इस चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते है। इस पूरी चयन प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के जिम्मेदार योग्य उम्मदीवारों को भर्ती प्रक्रिया से एन केन तरीके अपना कर दूर रखकर अपने निकटतम या जिनके साथ उनकी भ्रष्टाचार की जुगलबंदी हो चुकी है उन्ही का चयन करना चाह रहे हैं।

ऐसे करना चाह रहे हैं चयन प्रक्रिया में जिम्मेदार खेल

अतिथि शिक्षक वर्ग की निकली भर्ती प्रक्रिया को प्राचार्यों द्वारा न तो विज्ञप्ति चस्पा करवाई,न तो उम्मीद्वारो के आवेदन ग्रहण किए जा रहे है, तो वहीं उनसे कहा जा रहा है पद ही खाली नही है। इसके पीछे शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का सीधा सा उद्देश्य उन्ही लोगों को खाली पदों की जानकारी प्रदाय करना है और उन्ही के आवेदन ग्रहण करना है जिनका चयन उनको करना है। ऐसे दो मामले तो हमारे ही संज्ञान में आ गए जिसमें एक आवेदक जया सोलंकी जो कई बार खच्चर टोड़ी स्कूल में अपना आवेदन जमा करवाने गई तो पहले उनका आवेदन जमा करने से यह कहते हुए इनकार किया गया कि, जो आवेदन आए वो खंड शिक्षा अधिकारी के यहां भेज दिए गए हैं। जबकि आवेदन फॉर्म जमा करने का दूसरा ही दिन शुरू हुआ था और अंतिम तारीख आई भी नही थी। जबकि जया सोलंकी का स्कोर 189 था जो काफी उच्च होता है । फिर जब हमने उनसे इस संबंध में सबंधित स्कूल के प्रभारी से संपर्क साधा तो उसके बाद उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया।

इसी तरह मेघनगर कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी निसार पठान का ये कह कर आवेदन स्वीकार नहीं किया गया कि, उनका नाम पुरानी पैनल में पहले से ही है। नए आवेदकों के आवेदन अस्वीकार करने के बारे में पूछने पर कहा गया कि, सबका स्कोर हमको ऑनलाइन दिखता है हम उनमें से मेरिट के आधार पर चयन करेंगे। जबकि ऑनलाइन उन्ही का स्कोर दिखाता है जो कभी वर्ग 1,2,3 की अतिथि शिक्षक की जॉब कर चुके हो। साथ ही प्राचार्य जी एस देवहारे द्वारा कहा गया कि, पुराने अतिथि शिक्षको का ही चयन करना है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो फिर हमने प्रश्न किया जब पुराने ही रखने का आदेश था तो चयन प्रक्रिया पुराने पैनल में से होगी अभी आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो खामोश हो गए। कुल मिलाकर सारा मैच फिक्सिंग का खेल है जिसमे ब्लॉक के सभी प्राचार्य और जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी अपने करीबी अयोग्य लोगो का चयन पर्दे के पीछे हुए भ्रष्टाचार की आड़ में करने की कोशिश कर रहें है और देश के भावी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की जा रही है।

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी क्यू नही है

भर्ती प्रक्रिया की सबसे पहले विज्ञप्ति प्रकाशित होना था जिसमें कितने पद कहा-कहा हैं, ओपनिंग ,क्लोजिंग डेट कब तक है, आवेदकों को आवेदन कहा जमा करने होंगे स्पष्ट होना था। आवेदन जमा होने के बाद हर स्कूल में एक सूची चस्पा होनी चाहिए की कितने आवेदकों ने आवेदन जमा किए । फिर मेरिट के आधार पर चयन होने के बाद उच्च से निम्न स्कोर के साथ सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची चस्पा होनी चाहिए। इस तरह पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। मगर प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की बजाए अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, की तर्ज पर काम कर रहे है। विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारी का जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है की असली खेल क्या हो रहा है।

कलेक्टर को उठाना चाहिए सख्त कदम

अतिथी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला बच्चो के साथ ही देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योकि जितने उच्च कोटि के शिक्षको का चयन भर्ती प्रक्रिया से होगा जिले की स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी उतना ही उच्च होगा। जिसको लेकर जिला कलेक्टर को चाहिए की वो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने हेतु सख्त निर्देश दे और गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। जिससे लोगों को न्याय और प्रशासन में विश्वास दृढ़ हो सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422